साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025
हम दिखाएंगे आईना...
वर्ष : 01 अंक : 06 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए
www.shaharsatta.com

पेज 10 में...
MLA बनते ही "खामोश"

पेज 12 में...
जीरो टॉलरेंस का बना सिस्टम

पेज 03 खून-खराबा छोड़ेंगे तो...

'नान' में नए चांवल के बदले पुराने चांवल का बड़ा खेल

पीडीएस सिस्टम हाईजैक...

मुख्य संवाददाता
मो. ७०००६८१०२३

शहर सत्ता टीम/रायपुर/बालोद। एक बार फिर बीजेपी सरकार के सुशासन और डबल इंजिन की सरकार को मार्कफेड तथा नान की वजह से पलीता लग रहा है। नए चांवल के बदले मिलर्स द्वारा पुराने चांवल को खपाने का गोरखधंधा अब खुलकर शुरू हो गया है। खासकर बालोद, खैरागढ़ और रायपुर के सेंटरों में तो नए चांवल और पुराने चांवल का यह खेल बाकायदा खाद्य मंत्री की नाक के नीचे अंजाम दिया जा रहा है।

खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के साथ उनके पीए संतोष अग्रवाल परिलक्षित हो रहे हैं

★ **नहीं टूट रही नागरिक आपूर्ति निगम के जिम्मेदारों की कुंभकरणीय नींद**

★ **बालोद, खैरागढ़ और रायपुर के सेंटर में चलता है संतोष का सिस्टम**

★ **खाद्य मंत्री के पीए और नान के डिप्टी एजीएम के प्रेशर गेम से 3 ओएसडी हटे**

विभागीय सूत्रों के मुताबिक नान के डिप्टी एजीएम और विभागीय मंत्री दयालदास बघेल के पीए. संतोष अग्रवाल का पूरा सिस्टम प्रभावी है। गड़बड़ियों और बेजा वसूली की शिकायतें भाजपा संगठन से लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक से की गई है। बावजूद इसके संतोष अग्रवाल के प्रभाव से मंत्री के तीन ओएसडी क्रमशः अजय यादव, दिलीप अग्रवाल, संजय गंजघाटे (फ़िलहाल इस्तीफा दे चुके हैं) अब तक सिस्टम के शिकार होकर चलता कर दिए गए पर करोड़ों की अफरा-तफरी और वसूली बंद नहीं हुई। बताते हैं कि नान के डिप्टी एजीएम और खाद्य मंत्री के पीए पूर्व में तेजतर्रार मंत्री रहे अजय चंद्राकर के यहां भी थे और बेआबरू होकर रवाना भी कर दिए गए थे। मामला विधानसभा में उठ चूका है समिति भी गठित की गई है और जांच के लिए बैठकों का दौर भी बदस्तूर जारी है, बस कार्रवाई की कसर बाकि है।

इन सेंटरों में ज्यादा गड़बड़ियां

बालोद जिले के सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाले सेंटरों में डौंडी, डौंडी-लोहरा, का नाम बदनाम है। इसी तरह बालोद के ही गुंडरदेही(मटेवा) और चितौद सेंटर हैं। खैरागढ़ और रायपुर सेंटर भी लेव्ही वसूली में टॉप पर हैं। सूत्रों की मानें तो बालोद से 45 करोड़ क्वालिटी पर, रायपुर से तकरीबन 100 करोड़ की वसूली होती है। इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका शहर सत्ता कोई दवा नहीं करता लेकिन अगर ऐसा है तो एक उच्च स्तरीय जांच समिति से प्रति क्विंटल 5 रूपये लेव्ही वसूली और चांवल की क्वालिटी की जाँच होनी चाहिए।

"चावल घोटाले की जांच के लिए बैठकें हुई हैं। समिति अपनी जांच रिपोर्ट बना रही है। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।"

-पुन्नूलाल मोहले, पूर्व खाद्य मंत्री

एक व्यक्ति की 5 मलाईदार पदों पर तैनाती क्यों ?

नान में एकाधिकार और करप्शन की मुख्य वजह है एक ही व्यक्ति को मलाईदार जिम्मेदारियां और काबिल तथा अनुभवी अफसरों को हाशिये में रखना है। देखें तो वर्तमान में संदीप अग्रवाल और ज्योति सोनी जैसे अफसर की अनदेखी कर संतोष अग्रवाल को बेहिसाब विभाग सौंप दिया गया है। फ़िलहाल खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के चेहते पीए का प्रभार भी है और नान में डिप्टी एजीएम क्वालिटी कंट्रोल जैसे अहम् पद की कमान भी है। इतना ही नहीं संतोष अग्रवाल के पास कार्याधिकार में जनसूचना अधिकारी, फोर्टी फाइड चांवल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस), मक्का संबंधित सम्पूर्ण कार्याधिकार प्राप्त है। इन शार्ट कहा जाये तो नान में सबसे पावरफुल खाद्य मंत्री के पीए संतोष अग्रवाल के पास चांवल की गुणवत्तापूर्ण खरीदी से लेकर चांवल की गुणवत्ता और उसका सार्वजनिक वितरण तक का सर्वाधिकार है।

सुलगते सवाल

1. राशन दुकान के संचालकों ने लाखों का चावल बेच दिया, जांच अब तक सिफर
2. एक व्यक्ति को राशन देने में तकरीबन 5 से 10 मिनट टाइम लगता है
3. 1 दिन में 433 मिनट के अंदर 460 से ज्यादा को राशन वितरण कैसे
4. किस फर्जी अध्यक्ष ने गरीबों का चावल चोरी करके करोड़ों की संपत्ति बनाई
5. क्यों ईओडब्ल्यू में बेटे के साथ मिलकर हवाला का कारोबार करने वाले की नहीं हुई जांच
6. खाद्य अधिकारी, निरीक्षकों सहित नान के मैनेजर, ट्रांसपोर्टर सहित राशन दुकानदार बेख़ौफ़ क्यों?

साप्ताहिक शहर सत्ता

बालोद और डौंडी में इनके इशारे पर चलता है खेल

शालिनी गबेल, हेड ऑफिस में डिप्टी एजीएम के पद पर थी लेकिन प्रबंधक, बालोद पदस्थ कर गई हैं। दूसरे नंबर पर हर्षल मेश्राम क्वालिटी इंस्पेक्टर (बालोद एवं डौंडी) को धमतरी से बालोद यह 4 माह के एक्सटेंशन पीरियड को भी पूरा कर चुके हैं और पिछले 6 माह से मौखिक आदेश पर पदस्थ हैं। जबकि हर्षल मेश्राम का बालोद में पीएमओ तक से शिकायत हुई है। पीएमओ के पत्र के बाद इसका ट्रांसफर धमतरी किया गया था फिर उसे संतोष अग्रवाल के मौखिक आदेश पर बालोद ले आया गया है। तीसरा नाम है प्रमोद शर्मा कनिष्ठ सहायक गोदाम प्रभारी बालोद एवं डौंडी हैं। इनके खिलाफ राईस मिलर्स को धमकी, क्वालिटी से समझौता और बेजा वसूली का आरोप लगते रहा है। अध्यक्ष ताराचंद सांखला, सचिव आकाश कटारिया और कोषाध्यक्ष रतन लाल नाहटा जिला राईस मिल एसोसिएशन के हैं और इनके द्वारा ही टोकन जारी किया जाता है। कभी अगर कोई राईस मिलर्स सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है या पीएमओ से शिकायत करता है तो इनके द्वारा नान अफसर के इशारे पर मामला दबा दिया जाता है।

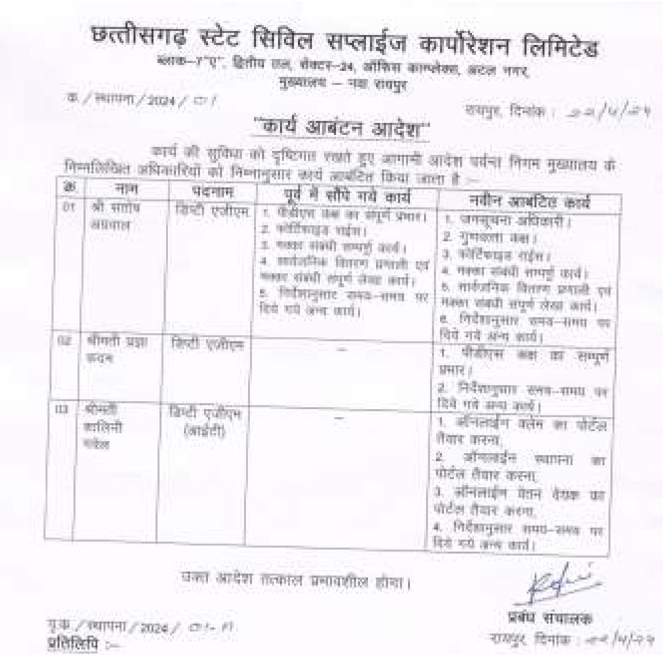
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
ब्लाक–7"ए", द्वितीय तल, सेक्टर–24, ऑफिस काम्प्लेक्स, अटल नगर,
मुख्यालय – नवा रायपुर

क्र./स्थापना/2024/ [illegible] रायपुर, दिनांक : [illegible]

"कार्य आबंटन आदेश"

कार्य की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आगामी आदेश पर्यन्त निगम मुख्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य आबंटित किया जाता है :–

क्र.	नाम	पदनाम	पूर्व में सौंपे गये कार्य	नवीन आबंटित कार्य
01	श्री संतोष अग्रवाल	डिप्टी एजीएम	1. [illegible] कक्ष का संपूर्ण प्रभार। 2. फोर्टिफाइड राईस। 3. गनका संबंधी सम्पूर्ण कार्य। 4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं [illegible] संबंधी सम्पूर्ण लेखा कार्य। 5. निर्देशानुसार समय–समय पर दिये गये अन्य कार्य।	1. जनसूचना अधिकारी। 2. गुणवत्ता कक्ष। 3. फोर्टिफाइड राईस। 4. गनका संबंधी सम्पूर्ण कार्य। 5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं गनका संबंधी सम्पूर्ण लेखा कार्य। 6. निर्देशानुसार समय–समय पर दिये गये अन्य कार्य।
02	श्रीमती प्रज्ञा [illegible]	डिप्टी एजीएम	–	1. [illegible] कक्ष का सम्पूर्ण प्रभार। 2. निर्देशानुसार समय–समय पर दिये गये अन्य कार्य।
03	श्रीमती शालिनी गबेल	डिप्टी एजीएम (आईटी)	–	1. ऑनलाईन [illegible] का पोर्टल तैयार करना, 2. ऑनलाईन स्थापना का पोर्टल तैयार करना, 3. ऑनलाईन वेतन [illegible] का पोर्टल तैयार करना, 4. निर्देशानुसार समय–समय पर दिये गये अन्य कार्य।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

प्रबंध संचालक
रायपुर, दिनांक : [illegible]

पृ.क्र./स्थापना/2024/ [illegible]
प्रतिलिपि :–

नान के कर्ताधर्ता एक अधिकारी को छोड़कर बाकि सब सिर्फ डमी

जन्मेजय महोबे, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम

(अधिकार क्षेत्र में बिना हताक्षर के पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन संतोष अग्रवाल के दबाव प्रेशर में सिर्फ दिन काट रहे हैं पिछले सालभर से)

श्रीमती ज्योति सोनी, डिप्टी जीएम प्रशासन

(पहले अनुभवी अधिकारी एवं स्थापना प्रमुख थीं अब पदावनत करके प्रशासन दे दिए हैं। इनका कार्यक्षेत्र इंक्रीमेंट, नोटशीट अदि कार्य हैं)

संदीप अग्रवाल, डिप्टी एजीएम नान

(अनुभवी विभागीय अधिकारी हैं शुरू से रेग्युलर पोस्ट पर हैं। पूर्व में नान के नोडल अधिकारी थे। वर्तमान में इनके पास कोई अहम् जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ डमी अधिकारी बना दिए गए हैं।)

संतोष अग्रवाल, डिप्टी एजीएम क्वालिटी कंट्रोल नान

(खाद्य मंत्री के पीए हैं, विभाग में पिछले 7 से 8 साल से नियमित हुए हैं। फ़िलहाल इनके जिम्मे में चावल की गुणवत्ता, क्वालिटी इंस्पेक्टरों अफसरों समेत निगम के सभी जिला प्रबंधक, कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में सीधा हस्तक्षेप रखते हैं।)

सिर्फ दो प्लेसमेंट एजेंसी से डिप्टी एजीएम को मोहब्बत

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के पीए और नागरिक आपूर्ति निगम के डिप्टी एजीएम संतोष अग्रवाल ही एकमात्र पावरफुल हैं जिन्हें दो प्लेसमेंट एजेंसियां ही पसंद आती हैं। इनमें से एक एजेंसी किसी राज बोथरा और नितीश भंडारी की 'कॉल मी सर्विसेस' टैगौर नगर रायपुर है तो दूसरी प्लेसमेंट एजेंसीं मेसर्स 'सिक्योर सर्विसेस' है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि दोनों ही एजेंसियां एक ही पार्टनर्स की हैं और इन्हें हर साल नाम बदलकर काम दिया जाता है। बता दें कि प्लेसमेंट एजेंसी से नान में अभी 36 क्यूआई, 60-70 सेंटर इंचार्ज, 50-60 प्रोग्रामर, 20-30 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 30 लेखा कर्मी है। प्लेसमेंट के जरिये पूर्व में एक-एक साल का होता था अभी ढाई साल का कार्यकाल कर दिया गया है।

धर्म-कर्म भी पीए के कहने पर

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल का उनके पीए संतोष अग्रवाल को इतना वरदहस्त प्राप्त है कि पीए के साथ दो बार तंत्र-मंत्र पूजा के लिए प्रख्यात मां कामाख्या मंदिर गए। एक तजा उदहारण है कल हनुमान जयंती का, जिसमें पीए के एक बार के अनुग्रह पर खाद्य मंत्री अपने गांव कुरा मुंगेली से राजधानी रायपुर स्थित डीईओ ऑफिस के हनुमान मंदिर आये पूजा-पाठ करवाए और फिर महज 10 मिनट में ही अपने गांव लौट गए। बताते हैं कि मंत्री के आने का कोई कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था और बंगला स्टाफ भी उनके आगमन से अनभिज्ञ था।

केमिकल जांच और सैंपल सील से होगा खुलासा

बालोद में ही अकेले 5 सेंटर(गोदाम) हैं। यहां नए चांवल के बदले मिलर्स द्वारा दिए गए पुराने चांवलों की केमिकल टेस्टिंग करवाने से बड़ी गड़बड़ियां सामने आएंगी। एक्सपर्ट्स की मानें तो क्वालिटी इंस्पेक्टरों की टीम से यहां रखे चांवल के नए या पुराने होने का टेस्ट होगा तो सबकुछ साफ हो जायेगा। वैसे विभाग के 92 क्यूआई.(गुणवत्ता निरीक्षक)भी एक ही थैले के चट्टे-बट्टे हैं। इसलिए उनसे चांवलों के सीलबंद सैंम्पल एकत्र करवाकर अगर शासन बाहर के लैब में जाँच करवाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

ऐसे होती है क्वालिटी टेस्टिंग

मिलर्स द्वारा भेजे गए गोदामों में रखे चांवल नए धान के हैं या पुराने के इसका पता लगाने एक केमिकल डालकर देखा जाता है। केमिकल डालते ही नया चांवल ग्रीन या लाइट ग्रीन हो जाता है। अगर चांवल पुराण या गुणवत्ताहीन या मापदंडों के विपरीत है तो फिर चांवल का रंग पीला या ऑरेंज हो जायेगा। एक्सपर्ट्स ने नाम नहीं छपने की शर्त पर बताया कि मार्कफेड से नया धन मिलर्स लेते हैं और डिफ्रेंस वेट को बराबर करने बाहरी राज्यों से पुरना चांवल खपाते हैं। इतना ही नहीं सिर्फ गोदामों में गड़बड़ी नहीं है बल्कि बालोद, खैरागढ़ और रायपुर की सरकारी राशन दुकानों में जांच होगी तो बड़ा खुलासा होगा।

मंत्री-विधायकों और रिश्तेदारों की राईस मिलें

छत्तीसगढ़ में तकरीबन 2840 राईस मील हैं। देखा जाये तो उसना और अरवा मिलकर लगभग 6258 राईस मिलें हैं। मजे की बात यह कि ज्यादातर राईस मील मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों और उनके रिश्तेदारों के नाम की हैं। नए और पुराने चांवल के इस खेल का सूत्रपात इन्हीं मीलों से होता है। अगर निष्पक्ष जांच शासन करवाए तो इन घोटालों में शामिल आंकड़ों का ग्राफ प्रति वर्ष 10 से 15 हजार करोड़ तक जायेगा। बता दें मार्कफेड से लेकर नान तक में भूपेश शासनकाल के समय धमतरी कुरुद के रौशन चंद्राकर पर एफसीआई चांवल को नान में कन्वर्ट करवाने का आरोप है। इसलिए ईडी के शिकंजे में जेल की हवा खा रहा है आरोपी रोशन। कस्टम मिलिंग का बीलिंग में आरोप गंभीर है।

गरीबों-किसानों के धान में यह खेल

नए धान का उठाव और पुराने चांवल की खपत के खेल में होता है बड़ा खेल। इसी तरह पुराने चांवल की गुणवत्ता में भी है बड़ा घोटाला। प्रति क्विंटल धान में अवैध लेव्ही वसूली 4 से 5 रुपये हो रही है। जानकारी के मुताबिक दो वेरायटी के ग्रेड 'ए' यानि पतला और कॉमन मतलब मोटा क्वालिटी चांवल को बांटा गया है। लेकिन शासन का ख़रीदा गया धान गायब कर पुराने और बाहरी राज्यों के चांवल को खपाने का यह खेल कई हजार करोड़ का गोरखधंधे में तब्दील हो चूका है। पूर्वर्ती शासनकाल से मार्कफेड और नान का मापदंड, गुणवत्ता का का पूरा सिस्टम ट्रांसपोर्टिंग से लेकर बारदाना खरीदी तक कटघरे में है।

जांच हुई तेज लेकिन कार्रवाई की रफ़्तार धीमी

प्रदेश में 219 करोड़ रुपए से ज्यादा के चावल घोटाले की जांच तेज हो रही है। घोटाले की जांच के लिए बनी विधानसभा समिति अब खाद्य विभाग के अफसरों से पूछताछ करेगी। पिछले बजट सत्र के दौरान चावल घोटाले के लिए गठित विधानसभा जांच समिति की बैठक 18 मार्च को हुई थी। जांच के लिए गठित समिति की सातवीं बैठक थी। समिति की पहली बैठक 12 अगस्त 2024 को हुई थी। इसके बाद चार, पांच, 30 सितंबर, 19 नवंबर, 11 दिसंबर 2024 को हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार, घोटाले में संचालनालय के अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आना तय बताया जा रहा है। पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले और दो पूर्व मंत्री राजेश मूणत और विक्रम उसेंडी सहित कांग्रेस के लखेश्वर बघेल व संगीता सिंह सदस्य है।

एक नजर में नागरिक आपूर्ति निगम

- नान तकरीबन 9 हजार करोड़ का सैटअप है।
- नान को कुछ सालों से राजस्व नुकसान हो रहा है।
- नुकसान की भरपाई नान को लोन लेकर करना पड़ रहा है।
- वर्ष 2013 यानि कि पिछले 13 सालों से स्थाई भर्ती नहीं
- नान का सारा कार्य प्लेसमेंट एजेंसी से चल रहा।
- नान में 33 जिलों का जिम्मा स्थाई 31 डीएम, करीब 90 क्यूआई हैं।

क्या सहीं पैमाने पर मिला रहे फोर्टी फाइड चांवल

कोरोना काल के समय केंद्र से मिलने वाला अतिरिक्त 5 किलो चांवल और राज्य सरकार से दिया जाने वाला 35 किलो चांवल गरीबों को मुफ्त में दिया जाता था। अब स्थिति यह है कि सिर्फ 35 किलो चांवल ही गरीबों को मुफ्त मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा क्या 5 किलो अतिरिक्त चांवल देने की योजना बंद कर दी गई है। क्या 35 किलो चांवल राज्य सरकार गरीबों को दे रही है या इसमें केंद्र सरकार का भी कोई अंशदान है? क्योंकि जब गोदाम से शासकीय दुकानों के लिए दो टाइप का चांवल जिसमें फोर्टी फाइड और नॉन फोर्टी फाइड चांवल आवंटित किया जाता है। गरीबों के 35 किलो चांवल में तकरीबन एक क्विंटल बोरी में एक किलो फोर्टी फाइड चांवल मिलाया जाता है। बता दें कि यह पीएम नरेंद्र मोदी की महती योजना कुपोषण मुक्त भारत के तहत फोर्टी फाइड चांवल मिलाया जा रहा है। चांवल के तौल और मापदंड पर सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नान के पास नहीं है।

नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति से 120 दिन के भीतर पुर्नवास की गारंटी

खून-खराबा छोड़ेंगे तो खुलेंगे विकास के द्वार

रायपुर। अब वक्त है हथियार छोड़कर कलम, खेती और अपने रुचि के रोजगार व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने का। छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर साथ देने को तैयार है। आत्म समर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 में की है। यह नई नीति राज्य से नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने और भटके हुए युवाओं को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए की गई है,ताकि वह समाज मे सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। वास्तव में नक्सलियों के पुनर्वास के लिए बनाई गई नई नीति में आत्मसमर्पण करने वालों के लिए अच्छे प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव की सरकार द्वारा लागू की गयी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 न सिर्फ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा देती है, बल्कि उन्हें पुनर्वास, रोजगार, और सम्मानजनक जीवन की गारंटी भी देती है। इस नीति के जरिए राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंसा के रास्ते पर चल रहे युवाओं के लिए अब समाज की मुख्य धारा में लौटने का दरवाज़ा पूरी तरह खुला है और वह भी सम्मान और भरोसे के साथ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने खुद आह्वान किया है कि जो भी युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और शांति की राह पर लौटना चाहते हैं, राज्य सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। नई नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को ट्रांजिट कैंप या पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा, जहां उन्हें उनकी रुचि के अनुसार किसी न किसी हुनर में प्रशिक्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, तीन साल तक हर महीने 10,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। आवास के लिए शहरी इलाके में प्लाट, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि, स्वरोजगार और व्यवसाय से जुड़ने की योजनाएं भी उनके लिए उपलब्ध रहेंगी। सबसे खास बात यह है कि आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया 120 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी, ताकि वे जल्द से जल्द समाज की मुख्यधारा में लौट सकें। यह नीति न केवल छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलियों पर लागू होगी, बल्कि अन्य राज्यों में सक्रिय नक्सलियों के लिए भी एक

- **एलएमजी के बदले मिलेंगे 5 लाख और एके-47 पर 4 लाख रुपये**
- **बड़े हथियार डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर एक लाख का ईनाम**

सुनहरा अवसर प्रदान करेगी, बशर्ते वे तय प्रक्रिया के तहत प्रमाणन और अनापत्ति प्राप्त करें। सरकार की यह पहल एक तरफ जहां राज्य में स्थायी शांति बहाल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है, वहीं दूसरी ओर यह संदेश भी देती है कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता — भविष्य निर्माण का रास्ता अब विकास, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन से होकर गुजरता है। राज्य और जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा आत्मसमर्पण के प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी वास्तव में समाज में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हनुमान जन्मोत्सव पर की पूजा-अर्चना

- **साय ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, कहा- बजरंग बली शक्ति और भक्ति के प्रतीक**

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा प्रदेशवासियों की सुख-शांति और समृद्धि के लिए मंगलकामनाएँ कीं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान हनुमान शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से हर संकट का समाधान संभव है। उन्होंने प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री निवास में की पूजा-अर्चना

श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास में विधि-विधान से भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना की. पूजा में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय सहित परिवारजन भी उपस्थित थे. उन्होंने भगवान हनुमान से छत्तीसगढ़ वासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संदेश में कहा कि प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों पर बरसता रहे।

बैसाखी पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैसाखी पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बैसाखी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह दिन सिख समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बैसाखी का पर्व हमें मेहनत, समर्पण और परिश्रम के मूल्यों की याद दिलाता है।

सुशासन तिहार में लापरवाही, पांच सीएमओ, तीन एसडीएम को नोटिस

गरियाबंद। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन तिहार के दौरान विभागवार प्राप्त आवेदनों का व्यवस्थित रूप से संकलन एवं एन्ट्री कर संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजे। जिससे कि संबंधित विभाग उन आवेदनों का निराकरण शीघ्रता से कर सके। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के एन्ट्री एवं निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी, अन्यथा संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों का एन्ट्री किया जा रहा है। उसके मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी लगाये। प्रत्येक आवेदनों का गंभीरतापूर्वक जांच उपरांत संबंधित विभाग को प्रेषित कर पावती प्राप्त करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सुशासन तिहार 2025 के तहत पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत आवेदकों से उनकी शिकायतों व मांगों को लेकर आवेदन प्राप्त किया गया है। जिसका निराकरण 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। अधिकारियों ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान जिले में कुल 1 लाख 45 हजार 984 आवेदन प्राप्त हुआ। कलेक्टर अग्रवाल सुशासन तिहार के तहत विगत दिनों क्षेत्र भ्रमण पर थे। इस दौरान फिंगेश्वर सीएमओ चंदन मानकर कार्यालय में अनुपस्थित पाये गये थे और मुख्यालय से बाहर थे।

व्यापारियों को राहत, दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 व नियम 2021 लागू

रायपुर। राज्य में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा नियम, 2021 को 13 फरवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश पर तैयार मॉडल शॉप एक्ट के अनुरूप है। यह अधिनियम राज्य के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। वहीं, जिन प्रतिष्ठानों में 10 से कम कर्मचारी हैं या कोई भी श्रमिक कार्यरत नहीं है, उन्हें इस अधिनियम से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार से जुड़े व्यवसायियों को मिलेगा, जिन्हें अब जटिल श्रम कानूनों की बाध्यता से राहत मिल जाएगी। नए अधिनियम के तहत पंजीयन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।

प्रभु यीशु मसीह के जयकारे के साथ 40 दिन का उपवासकाल संपन्न

रायपुर। राजधानी में रविवार को मसीही समाज ने पाम संडे यानी खजूर रविवार मनाया। इस मौके पर चर्चों से खजूर की डालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के जयकारे करते हुए जुलूस निकाले गए। गिरजाघरों को भी खजूर की डालियों व खजूर फल से विशेष रूप सजाया गया था। सोमवार से दुख भोग सप्ताह की शुरूआत हो रही है। प्रतिदिन संध्या चर्चों में बाइबिलविदों के प्रवचन होंगे। खजूर विवार के जुलूस की अगवाई छत्तीसगढ़ डायसिस की बिशप डॉ. सुषमा कुमार, डायसिस के सचिव नितिन लॉरेंस, पादरी सुनील कुमार, जुलूस के कन्वीनर जॉन राजेश पॉल ने की।

बिशप ने देश में शांति, एकता, भाईचारे, उन्नति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत प्रदेश व देश के अगुवों, दीन - दुखियों के लिए प्रार्थना की। विशेष रूप से पादरी सुबोध कुमार, पादरी सुशील मसीह व सेवकगण, डीकन मनशीष केजू, सचिव रूचि धर्मराज, कोषाध्यक्ष किरण सिंग, को-कन्वीनर शोमरोन केजू व प्रवीण जेम्स, पास्ट्रेट कमेटी के मेंबर प्रेम मसीह, नीरज राय व विनित पॉल, डीके दानी, दीपक गिडियन भी शामिल हुए। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एसएन राजू भी विशेष रूप से शामिल हुए। पास्ट्रेट कोर्ट के सदस्य अजय मसीह, डीके दास, एडवोकेट सरिता सिंग, मुकेश पौलूस, महिला सभा अध्यक्ष अनीता दास व पदाधिकारी, युवा सभा अध्यक्ष जेनिस दास, सचिव अनुदित रंजन व टीम, विजय मसीह, रूपिकी लारेंस, गजेंद्र दान, ऋचा जोगी, डिक्सन बैंजामिन, मोनू डेनिएल, राबर्ट दास, सौरभ देव, एनसी मिशैल, ज्ञानेद्र मसीह, रीना मसीह, सुरेश मसीह मसीही विकास समिति श्याम नगर, संडे स्कूल श्याम नगर, विनोबा भावे नगर, तेलीबांधा व राजातालाब के बच्चे व पदाधिकारी, सालेम स्कूल ,सेंट पॉल्स स्कूल, शामिल हुए।

साप्ताहिक शहर सत्ता

कांग्रेस ने लगाया साय सरकार पर आरोप
कन्हैरा में 50 से अधिक गायों की मौत

रायपुर। थाना उरला क्षेत्र अंतर्गत मेटल पार्क कन्हेरा श्मशान घाट के पास कुल छः गाय मृत अवस्था में पाए गए। मौके पर पुलिस द्वारा शव पंचनामा कार्यवाही की गई है। पशु चिकित्सक द्वारा सभी मृत छः गायों का पोस्टमार्टम किया गया है और परीक्षण हेतु एफएसएल भेजने बिसरा जप्त किया गया है। घटना स्थल के पास करीब 40-50 बोरी पशु आहार पड़ा हुआ था। पशु आहार के सैंपल जप्त किया गया है। प्रथम दृष्टया पशु आहार को खाने से गायों की मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। उरला थाना द्वारा कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम बिरगांव के टीम की मदद से सभी मृत गायों को पोस्टमार्टम के बाद दफन किया गया है।

गौठान योजना बंद किए जाने से बे-मौत मारे जा रहे हैं गौवंशी

राजधानी से लगे उरला के समीप ग्राम कन्हैरा मे 50 से अधिक गायों की मौत होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गाय और गोबर जैसे विषयों पर केवल राजनीति करती है। इन गायो की मौत साय सरकार की लापरवाही के कारण हुई है। सरकारी अमला सजग होता तो इतनी बड़ी संख्या मे गायों की मौते नहीं होती। राज्य मे भाजपा की सरकार बनने के बाद यह छठवीं घटना है ज़ब इतनी बड़ी संख्या मे गाय बेंमौत मरी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंशी पशु बदहाल हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बंद करके गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने छोड़ दिया गया है। जिसके चलते एक तरफ जहां किसान खुली चराई से परेशान हैं, वही सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ गई है। गौ अभ्यारण्य के नाम पर केवल वाहवाही लूटी जा रही है धरातल पर कुछ नहीं है। भाजपा की सरकार में गाय, भैंस के साथ जनता भी सड़कों पर बे मौत मरने मजबूर हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनकी ना कोई नीति है ना नियत, बल्कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं को भी दुर्भावना पूर्वक बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने छत्तीसगढ़ में 10 हजार से अधिक गोठान बनाए थे, जिसमें से लगभग 8 हज़ार गोठान आत्मनिर्भर बन चुके थे।

सीएम के सलाहकार पंकज झा ने महिलाओं का अपमान कियाः ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा का महिला सम्मान का नारा सिर्फ दिखावा और ढोंग है। जब मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज झा ही सोशल मीडिया में महिलाओं के खिलाफ गंदी-गंदी अभद्र टिप्पणी करते हैं और मुख्यमंत्री के बगल में खड़े नजर आते हैं ऐसे में महिलाओं की सम्मान की उम्मीद भाजपा नेताओं से करना बेमानी है और यह बात प्रदेश की जनता समझ चुकी है और जिस युवा ने बेबाकी से शिकायत दर्ज कराई है इसके बाद तत्काल मुख्यमंत्री को पंकज झा को सलाहकार पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सुशासन तिहार पर आम जनता का आक्रोश सामने आ रहा है आम जनता सरकार के कामकाज से नाराज है।

अबोध बच्ची से दुराचार हो रहा, किसान जूते से पीटा जा रहा, सरकार सुशासन तिहार मना रही - सुशील

कांग्रेस का आरोप- जनता के आवेदनो से सरकार की नाकामी सामने आई

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय सरकार किस बात का सुशासन तिहार मना रही है। राज्य में किसानों को जूते से पीटा जा रहा है सिर्फ इसलिए उसने मिल मालिक के अवैध कब्जा के खिलाफ आवाज उठाई थी। युवाओं को रोजगार के लिये अंगारो में चलना पड़ रहा है। राज्य की कानून व्यवस्था समाप्त हो गयी है। मासूम बच्ची के साथ दुराचार करके हत्या कर दी जाती है। राज्य में रोज हत्या, डकैती, बलत्कार हो रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में धान घोटाला हो जाता है। डबल इंजन की सरकार में भारत माला घोटाला हो जाता है। आत्ममुग्ध सरकार सुशासन तिहार मना रही है।

भाजपा सरकार के द्वारा मनाये गये सुशासन तिहार से सरकार की नाकामी सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सुशासन तिहार में जनता के द्वारा दिये जाने वाले आवेदनों की अंतिम तिथि पूरी हो गयी। जनता ने सरकार को जो आवेदन दिया है, उससे सरकार का दागदार चहेरा सामने आया है। सुशासन का दंभ भरने वाली साय सरकार के राज में आम आदमी छोटे-छोटे कामां के लिये सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर है।

पटवारी कार्यालय से लेकर तहसील दफ्तरों में लोगो के नामांतरण, फौत, त्रुटि सुधार के लाखो आवेदन लंबित है, लोगों के काम नहीं हो रहे, आम आदमी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। साय सरकार लोगो के मूलभूत काम को भी नहीं कर पा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सुशासन तिहार में बेरोजगार युवको का साय सरकार के प्रति गुस्सा भी खुलकर सामने आया है। एक बेरोजगार युवक ने तो वित्त मंत्री को हटाने की मांग का आवेदन सौंपा है। मुख्यमंत्री इस बेरोजगार युवक की मांग पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे।

धर्मांतरण भाजपा के लिये राजनैतिक हथियार वह निदान नहीं चाहतीः बैज

रायपुर। धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री साय धर्मांतरण

पर केवल बयान देते है। राज्य में जब से भाजपा की सरकार बनी है प्रदेश के शहरी एवं मैदानी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण की घटनायें बढ़ गयी है। भाजपा खुद धर्मांतरण को बढ़ावा देती है फिर वर्ग संघर्ष करवाती है विपक्ष में रहते हुये धर्मांतरण के नाम पर फसाद करने वाले भाजपाई पिछले एक साल से प्रदेश में होने वाली धर्मांतरण की घटनाओं पर चुप्पी साध लिये है। यही नहीं खबरें तो यह भी आ रही है कि धर्मांतरण कराने वालों को सत्तारूढ़ दल का संरक्षण मिला हुआ है। जशपुर, बस्तर में धर्मांतरण की घटनाओं के बाद भाजपा की खामोशी इस बात का प्रमाण है कि इन घटनाओं को उसका समर्थन है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने अपनी पहली बैठक में ही वह दावा किया था कि नया "धर्म स्वातंत्र विधेयक" का ड्राफ्ट तैयार है, 60 दिन के भीतर लागू हो जायेगा, लेकिन सवा साल बीतने के बाद आज तक मौन है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा जनता पार्टी की जब-जब प्रदेश में सरकार रहती है वे स्वयं धर्मातरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पर बयानबाजी करके मत का ध्रुवीकरण कर सके।

6 लाख अनियमित कर्मचारियों को कब मिलेगा न्याय : आप

रायपुर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डॉ. संदीप पाठक जी ने प्रेसवार्ता में छत्तीसगढ़ कि भाजपा सरकार पर बेरोजगारी पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जो बेरोजगारी की विकराल समस्या से जूझ रही है उसे रोजगार कब मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इससे पहले की कांग्रेस की सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गयी थी, जनता ने फिर भाजपा पर भरोसा कर भारी मतों से चुना। लेकिन राज्य की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पायी,किसी से पूँछ लो किसी को नहीं मालूम की सरकार कौन चला रहा है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। राज्य में अभी तक 2 मंत्री का पद तक नहीं भर पाए। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य या देश में समृद्धि और सुख का मूल परिचायक रोजगार से होता है। पिछली सरकार में बेरोजगारी के आंकड़ों में खेल किया, आज प्रदेश में 1692824 बेरोजगार हैं, लगभग 17 लाख बेरोजगार हैं। 63000 शिक्षा विभाग में पद खाली है, 5500 स्कूल में 1 शिक्षक नहीं हैं,वहीं रायपुर में में ही 27 स्कूल हैं जहाँ 1 ही शिक्षक हैं और 610 स्कूल हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में 11 साल से शिक्षकों की वरिष्ठता की सूची नहीं निकाल पाए हैं. 8 वीं तक तो बच्चों को ग्रेस से पास करा दिया जाता है और 9वीं के बाद 90 प्रतिशत रिजल्ट लाने का प्राचार्यो पर दबाव रहता है, शिक्षा को राज्य में शिक्षा को मज़ाक बना कर रख दिया है। 10 मेडिकल कॉलेज में 642 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली हैं,6 लाख अनियमित कर्मचारी हैं,उनका epf तक नहीं काटा जा रहा है,इनके लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है कि इनको नियमित कैसे किया जायेगा।

संपादकीय

◦ सुकांत राजपूत

दिन बहुरेंगे

केंद्र और राज्य की डबल इंजिन सरकार भारत समेत देश के नए राज्यों को भी एक बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाने की कोशिशों में जुट गई है। अब हमारे छतीसगढ़ और हर एक छत्तीसगढ़िया के लिए उन्नति, विकास और रोजगार के किवाड़ भी खुलने लगे हैं। महज चंद घंटों पहले सुशासन के ध्योतक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट और प्रोडक्शन के लिए 1143 करोड़ रुपए की पूरी यूनिट का भूमिपूजन किया है। छत्तीसगढ़ जैसे युवा राज्य के लिए यह साय सुशासन की ऊर्जावान पहल छत्तीसगढ़ के लिए नया भविष्य गढ़ रही है। बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाने के इन प्रयासों से निश्चित ही प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। राज्य समेत भारत दुनिया के कई क्षेत्रों में अगुवा भी बनेगा। भारत अपने बड़े संसाधनों और कुशल कामगारों का इस्तेमाल करके विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनने का माद्दा भी रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 से 2024 के बीच भारत ने 667.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) आकर्षित किया है।

भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया वाहन निर्माता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और वाहन जैसे क्षेत्रों के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के प्रयास जापान की कंपनियों के लिए यहां निवेश के नए अवसर खोल रहे हैं। भारत विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के निष्कर्षण जैसे अग्रणी क्षेत्रों के लिए उद्योग-विशिष्ट प्रोत्साहन और वित्तीय पैकेज प्रदान करना। युवा और तेजी से समृद्ध होते मध्यम वर्ग द्वारा संचालित भारत का विशाल घरेलू बाजार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन कलपुर्जा से लेकर स्वास्थ्य सेवा और खाद्य प्रसंस्करण तक सभी क्षेत्रों में मजबूत आंतरिक मांग सुनिश्चित करता है।

मोदी सरकार का 'मेक इन इंडिया' पहल, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और हरित विनिर्माण शामिल हैं। मेक इन इंडिया पहल को एक दशक पूरा हो चुका है। मेक इन इंडिया योजना का मकसद भारत को मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। यानी भारत का जोर नवाचार और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने पर है। छत्तीसगढ़ राज्य को भी नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकियों और उन्नत विनिर्माण में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ सुनिश्चित करने मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार की पूरी टीम भी दिल, दिमाग और शरीर से जुट गई है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत औद्योगिक उत्पादन का केंद्र होगा और जल्द ही प्रदेश का नाम भी नवाचार और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने वाला होगा।

आतंकवाद को अब बिरयानी नहीं परोसेंगे...

सुनील दास, वरिष्ठ पत्रकार

कोई काम जब पहली बार किसी देश में होता है तो वह देश व देश के लोगों के लिए बड़ी बात तो होती है। भारत पहली बार एक आतंकवादी को पकड़कर सजा देने के लिए लाने में सफल हुआ है तो यह देश की सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि तो है। जनता सरकार इस बात के लिए सरकार की तारीफ तो करेगी ही कि मोदी सरकार ही पहली ऐसी सरकार जिसने मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड को पकड़कर देश लाने में सफल हुई है। कई आतंकवादी भारत में आतंकवादी हमला कर पाकिस्तान या विदेश भाग जाते हैं, उन्होंने भारत में अपराध किया है, वह भारत के गुनहगार हैं लेकिन कई बार किसी देश से प्रत्यर्पण संधि नहीं होने पर उस देश से देश के अपराधी को पकड़कर लाना संभव नहीं होता है। किसी देश से प्रत्यर्पण संधि होने पर उस देश के कानून, उसे देश से भारत के संबंध कैसे हैं,उस देश के अपने राजनीतिक हित के चलते अपराधी को देश पकड़कर लाना आसान नहीं होता है।

पीएम मोदी के ट्रंप से अच्छे संबंध के चलते ही पाकिस्तानी आतंकवादी तहव्वूर राणा को अमरीका से भारत लाना संभव हो सका है फिर भी इसमें करीब करीब 16 साल लग गए हैं। तहव्वूर राणा पाकिस्तानी सेना में डाक्टर था,हालांकि हमले के बाद उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली थी। लेकिन यह बात को सभी को पता है कि पाकिस्तान के कहने पर ही उसने मुंबई में आतंकवादी हमला करवाया था इसलिए पाकिस्तान भी परेशान है कि तहव्वूर राणा पर भारत में मुकदमा चलेगा तो फिर एक बार विश्व में इस बात की चर्चा होगी कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है और उनका उपयोग पड़ोसी देश भारत में आतंक फैलाने के लिए करता है।

वैसे भी पीएम मोदी के चलते पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बदनाम है और बहुत सारे देशों से पहले की तरह मदद नहीं मिलती है। वह आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण विश्व अकेला पड़ गया है। तहव्वूर राणा को अमरीका से भारत लाए जाने का देश की राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है। किसी दूसरे देश से आतंकवादी को पकड़कर भारत लाना और उस पर मुकदमा चलाकर सजा देने का यह पहला मामला है, मोदी सरकार तो इसका श्रेय लेगी ही कि पहली बार जो सरकार किसी आतंकवादी को किसी दूसरे देश से पकड़कर लाने में सफल हुई है तो वह मोदी सरकार है। इस आधार पर पीएम मोदी व भाजपा फिर देश में माहौल बनाएंगे कि मोदी सरकार ही ऐसी सरकार जो विदेश से आतंकवादी को पकड़कर ला सकती है और सजा दिला सकती है। तहव्वूर राणा से पूछताछ में भी कई बाते सामने आएंगी। यानी आने वाले दिनों तहव्वूर राणा कई दिनों तक चर्चा में रहने वाला है।

भाजपा इसका राजनीतिक फायदा बिहार चुनाव में उठा सकती है इसलिए कांग्रेस भाजपा को तहव्वूर राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय अकेले भाजपा को नहीं लेने देना चाहती है। जैसे ही यह खबर आई कि तहव्वूर राणा को भारत लाया जा रहा है तो कांग्रेस ने चिदंबरम को सामने किया और खुद भी श्रेय लेने लगी कि यूपीए सरकार ने भी तो तहव्वूर राणा के प्रत्यर्पण के लिए कोशिश की थी, यूपीए सरकार की कोशिशों के कारण ही आज तहव्वूर राणा को भारत लाया जा सका है। हकीकत यह है कि तहव्वूर राणा के प्रत्यर्पण में मिली सफलता सिर्फ कानूनी जीत नहीं है,यह अमरीकी अदालतों में सावधानी से दिए गए दलीलों व कूटनीतिक प्रयासों का नतीजा है। चर्चा है कि अमरीका में राणा की कानूनी टीम ने भारत को प्रत्यर्पण के विरोध में तर्क दिया था कि राणा पर पहले से ही संबंधित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है। इसलिए उस पर भारत में फिर से मुकदमा चलाना गैरकानूनी होगा। इस पर भारत की कानूनी टीम ने यह तर्क दिया था कि भारत में राणा पर मुकदमा दूसरे मामले में चलाया जाएगा तब जाकर अमरीका से उसका प्रत्यर्पण संभव हो सका है।

कांग्रेस कितना ही तर्क दे ले कि उसने भी प्रत्यर्पण के लिए कोशिश की थी या उसने दाऊद गैंग के अबू सलीम का प्रत्यर्पण कराया था लेकिन कांग्रेस को राणा के प्रत्यर्पण का जरा सा श्रेय भी मिलने से रहा क्योंकि इस बात की घोषणा तो तब की गई थी जब मोदी व ट्रंप एक मंच पर थे। इसके बाद तय हो गया था कि देरसबेर राणा का प्रत्यर्पण तो होना ही और यह अब जाकर 2025 में संभव हो सका है। यह भी ऐसे समय हुआ है जब कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में बिहार चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाई है कि जाति जनगणना,आरक्षण पचास प्रतिशत और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे को जब उठाती है तो देश में कोई राजनीतिक दल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कसाब के मामले में भाजपा ने सिर्फ एक लाइन कहा था कि कांग्रेस ने कसाब को जेल में बिरयानी खिलाती थी और इसका कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान हुआ था। इसके अलावा मोदी सरकार ने जब पाक में चल रहे आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया था तो पीएम मोदी की छवि ऐसे नेता की बनी थी कि वह तो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने वाले नेता हैं। इसका भी चुनाव में भाजपा को फायदा हुआ था। तहव्वूर राणा को भारत लाया जा चुका है, अभी कई महीनों उस पर मुकदमा चलना है,उसके बाद उसको सजा होनी है, यह सजा यदि बिहार चुनाव के आसपास होती है तो इसका लाभ निश्चित रूप से भाजपा को होगा।

देश में आतंकवाद व अलगाववाद को खत्म करने का श्रेय तो उसे मिल चुका है। इस वजह से वह मजबूत सरकार मानी जाती है। तहव्वूर राणा को सजा होती है तो मोदी सरकार को इस बात का श्रेय भी मिलेगा की उसने आतंकवादी को भारत में लाकर सजा दिलाई है। इससे जनता के बीच फिर एक बार संदेश जाएगा कि मोदी सरकार वाकई में मजबूत सरकार है। वैसे तो देश में लोग यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जाते हैं तो वह भी मोदी सरकार सुपारी देकर हत्या करवाती है। यानी जनता मानती है कि पीएम मोदी आतंकवादियों को उनके देश में मरवा सकते हैं, विदेश से लाकर देश में सजा भी दिलवा सकते हैं।

अरे भाई दम घुट रहा....

सिर्फ दुनिया ही नहीं भारत और इसके नए राज्यों में प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर है। दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 13 भारत के ही हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली दूसरे स्थान पर है। भारत में जल के लगभग 70 प्रतिशत स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं। बढ़ते प्रदूषण से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया को हर साल 8.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। वायु प्रदूषण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित हाशिए पर पड़े लोगों को असमान रूप से प्रभावित करता है। प्रदूषण की वजह से दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में 6.1 फीसदी की कमी आती है। साथ ही हर साल 1.2 बिलियन कार्य दिवसों का नुकसान होता है।

देश में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण पर नजर रखने के लिए 2018 में प्रदूषण नियंत्रण योजना शुरू की गई थी और इसके लिए पूरी राशि सरकार ही उपलब्ध करा रही है। सरकार का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5.4 फीसदी वायु प्रदूषण पर खर्च करता है,

लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2024-25 में 858 करोड़ रुपये के बजट का केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के अभाव में उपयोग नहीं हो सका। चालू वित्त वर्ष समाप्त होने वाला है, ऐसे में यह स्थिति प्रदूषण को लेकर लापरवाह रवैया एवं ठोस योजना के अभाव की तरफ इशारा कर रही है।

संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक हैरत की बात है कि पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार ने 858 करोड़ रुपये में से एक प्रतिशत भी पैसा खर्च नहीं किया। प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों को वित्तीय सहायता और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लिए पैसे मुहैया कराता है, जिसका उद्देश्य 131 अत्यधिक प्रदूषित शहरों में प्रदूषण को 40 प्रतिशत तक कम करना है। वास्तव में भारत में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पिछले कई वर्षों से वैश्विक सुर्खियों में रही है।

देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखना चाहिए और इसमें किसी प्रक्रियात्मक देरी जैसे अनुमति मिलने में देरी की भी गुंजाइश नहीं है। ऐसे में संसदीय समिति की रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। सवाल उठता है कि ऐसी योजना के लिए अनुमति समय रहते क्यों नहीं मिलती है, विशेषकर जब देश के शहरों में प्रदूषण गंभीर स्तरों तक पहुंच चुका है। कहा जा सकता है कि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए आवंटित राशि का सही तरीके से उपयोग किया जाना बेहद आवश्यक है। यदि इस स्थिति में सुधार नहीं किया गया, तो प्रदूषण का स्तर और भी गंभीर हो सकता है।

बर्फीली वादियों में दौड़ेगी वंदे भारत

क्यों खास है कश्मीर वाली वंदे भारत?

यह वंदे भारत एक्सप्रेस विश्वसनीयता, सुरक्षा और यात्रियों के आराम को सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक एवं उन्नत सुविधाओं से युक्त है। इस वंदे भारत ट्रेन को कश्मीर घाटी की कठिन जलवायु परिस्थितियों में सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिससे अब हर मौसम में कश्मीर घाटी तक पहुंचना आसान होगा और वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, क्षेत्र में यात्री सेवाएँ एवं पर्यटन अनुभव बेहतर बनाएगी।

श्रीनगर। अप्रैल की हल्की ठंडक और वसंत की खिलती बहार... हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, सेब के पेड़ों पर गुलाबी फूलों की चादर, और मैदानों की हरी घास — यह सब अब सिर्फ कल्पना नहीं रहेगा। क्योंकि अब जल्द ही, यह सब आप अपनी आंखों के सामने, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल डिजाइंड वंदे भारत ट्रेन में बैठकर देख सकेंगे। जैसे ही ट्रेन पहलगाम की घाटियों से गुजरेगी, हरियाली से सजी वादियाँ, दूर तक फैले चीड़ के जंगल और चरवाहों की झलक आपको एक लम्हे में रोक देंगे। देवदार की खामोशी को चीरती वंदे भारत की रफ्तार — तकनीक और प्रकृति का अद्भुत संगम जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। "मेक इन इंडिया" के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में बनी यह ट्रेन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है, जो बिजली सी चलती है। इसका सफर हर भारतीय को गर्व से भर देगा।

विशेष तकनीकी सुविधाएं

जम्मू-कश्मीर जैसे सर्द मौसम वाले क्षेत्र में सुचारू रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस वंदे भारत ट्रेन में विशेष तकनीकी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं:

सिलिकॉन हीटिंग पैड: यह वॉटर और बायो-टॉयलेट टैंकों में पानी को जमने से रोकेंगे। साथ ही, इनमें ओवरहीट प्रोटेक्शन सेंसर लगे हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि शून्य या माइनस तापमान में भी रेल संचालन सुचारू रूप से हो।

हीटेड प्लंबिंग पाइपलाइन: जीरो डिग्री से भी कम तापमान में सेल्फ-रेगुलेटेड हीटिंग केबल्स पानी को जमने से रोकेंगे।

ऑटो-ड्रेनिंग मैकेनिज्म: प्लंबिंग लाइनों में पानी के जमने की समस्या को रोकेगा, जिससे संचालन सुचारू होगा।

एंबेडेड हीटिंग एलिमेंट: फ्रंट लुकआउट ग्लास में लगाए गए यह एलीमेंट सर्द मौसम में विंडशील्ड को डी-फ्रॉस्ट कर ड्राइवर को क्लियर विज़न प्रदान करेंगे, जिससे सुरक्षित व सुगम ट्रेन संचालन हो सकेगा।

एंटी-स्पॉल लेयर: बर्फबारी या आंधी जैसे कठिन मौसम के दौरान यह लेयर ड्राइवर को सुरक्षित ट्रेन के संचालन में सहायता करेगा।

भारतीय रेल की न्यू-एज टेक्नोलॉजी

- **एयर ड्रायर सिस्टम हीटिंग:** अत्याधिक ठंड में एयर ब्रेक सिस्टम की दक्षता बनाए रखेगा। साथ ही, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) डक्ट्स द्वारा यात्रियों की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की गई है।
- **5 kVA ट्रांसफॉर्मर:** ट्रेन के महत्वपूर्ण घटकों के सुचारू संचालन और ठंडे मौसम में उनकी दक्षता बनाए रखने के लिए इसे अंडरफ्रेम में विशेष रूप से स्थापित किया गया है।
- **पूर्ण वातानुकूलित कोच:** सेमी-हाई-स्पीड क्षमताओं (160 किमी प्रति घंटे) से लैस होंगे, जिससे तीव्र और समयबद्ध यात्रा संभव होगी।
- **आधुनिक सुविधाएँ:** चौड़े गैंगवे, स्वचालित प्लग डोर, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, इंफोटेनमेंट सिस्टम और सीसीटीवी जैसी सुविधाएँ यात्रियों के अनुभव को सुगम बनाएंगी।

यात्रा में विकास का अनुभव

कश्मीर घाटी में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत रेल यात्रा में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह सेवा सभी मौसमों में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी, जो बर्फबारी, कठोर ठंड और कठिन पर्वतीय चुनौतियों को पार कर सुगम यात्रा का भरोसा दिलाती है। आधुनिक सुविधाओं और जलवायु-विशिष्ट अनुकूलन के साथ, यह ट्रेन यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। कश्मीर घाटी को सम्पूर्ण देश से अभूतपूर्व रूप से जोड़ने के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस भौगोलिक और आर्थिक अंतर को भी समाप्त करेगी।

12 हजार साल बाद डायर वुल्फ का 'पुनर्जन्म'

नई दिल्ली। अमेरिका के डलास शहर से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। डलास स्थित बायोटेक फर्म कोलोसैल बायोसाइंसेज ने विलुप्त हुए जानवरों को लेकर एक जरूरी एलान किया है। कोलोसैल बायोसाइंसेज ने विलुप्त हो चुके जानवरों को फिर वापस लाने के अपने मिशन में सफलता हासिल की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने सोमवार को बताया कि उन्होंने तीन डायर वुल्फ (Dire Wolves) को फिर से जीवित किया है। डायर वुल्फ पॉपुलर सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' में देखे गए थे, लेकिन पृथ्वी से इस प्रजाति को विलुप्त हुए 12 हजार सालों से ज्यादा समय हो चुका है। कोलोसैल ने 2022 में उस समय सुर्खियां बटोरी थीं जब उसने विलुप्त हो चुके वूली मैमथ को वापस लाने का लक्ष्य घोषित किया था। हालांकि तब तक कंपनी सिर्फ वूली चूहे को ही वापस लाने में सफल हो पाई थी।

कैसे हुआ यह मुमकिन?

कोलॉसल ने अपनी नई उपलब्धि के बारे में बताते हुए कहा, "इस तकनीक से डायर वुल्फ के तीन बच्चों का जन्म हुआ है, जिनमें दो नर, रेमस और रोमुलस हैं और खलीसी नाम की एक मादा वुल्फ है, जिनका वजन 80 पाउंड है।" आपको बता दें कि खलीसी नाम लोकप्रिय सीरीज 'गेम ऑफ थ्रोन्स' की एक किरदार पर रखा गया है।

डायर वुल्फ के इन बच्चों को अमेरिका की एक गुप्त लोकेशन पर रखा गया है। यह तीनों खाने में खास किबल (जानवरों के लिए बनाया खाना) के साथ गाय, हिरण और घोड़े का मांस खाते हैं। दोनों नर डायर वुल्फ, अपने सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार, ग्रे वुल्फ के बच्चों से लगभग 20 से 25% बड़े हैं। कोलोसल का अनुमान है कि पूरी तरह से बड़े हो जाने पर इन डायर वुल्फ का वजन करीब 140 पाउंड तक पहुंच जाएगा।

इन जानवरों को वापस लाने की तैयारी

कंपनी का उद्देश्य लंबे समय से विलुप्त हो चुके जानवरों- जैसे डोडो और तस्मानियाई टाइगर को वापस लाना है। कोलॉसल का दावा है कि वो अब तक रेड वुल्फ (लाल भेड़िए) के भी दो लिटर को क्लोनिंग के जरिए जन्म देने में सफल हुआ है- जो दुनिया के सबसे लुप्तप्राय भेड़ियों में से एक माने जाते हैं। हालांकि प्राकृतिक दुनिया से इस तरह की छेड़छाड़ को लेकर नैतिक सवाल भी उठ रहे हैं।

सभी धर्म एक हैं तो धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत : मोहन भागवत

धरमपुर में गरजे आरआरएस प्रमुख

धरमपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सभी धर्म एक है तो धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? मोहन भागवत ने शनिवार (12 अप्रैल) को गुजरात के वलसाड जिले का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने धरमपुर के बरुमाल धाम में श्री भावभावेश्वर महादेव मंदिर के रजतोत्सव कार्यक्रम में भी भाग लिया.

सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा, "सभी धर्म एक है तो धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? धर्मांतरण करने के पीछे का उद्देश्य समूह की शक्ति बढ़ाकर सत्ता पाने के लिए होता है. अपना प्रभाव बढ़ाना, अपनी शक्ति बढ़ाना, अपना विस्तार करने का मतलब धर्मांतरण की भावना पैदा करना होता है."

उन्होंने आगे कहा, "मेरा विश्वास मेरे ईश्वर में है, आप अपने ईश्वर में विश्वास रखें, वह आप में है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं. इसलिए मतांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है." एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, "ईसाई या मुसलमान बनने का क्या मतलब है? अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू ही रहना चाहिए."

हम किसी से लड़ना नहीं चाहते- भागवत

RSS प्रमुख ने कहा, "लोगों को किसी भी लालच या डर के प्रभाव में आकर अपना धर्म को किसी भी हालत में नहीं बदलना चाहिए. जिंदगी में लालच या प्रलोभन लोगों को उनके धर्म से दूर कर सकती है, लेकिन धर्म ही सभी को खुशी की ओर लेकर जा सकता है." उन्होंने कहा, "हम एकजुट होना जानते हैं और एकजुट होना ही चाहते हैं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आज कई ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो यह चाहते हैं कि हम अपने आपको बदल दें तो ऐसी ताकतों से हमें खुद को बचाना होगा."

ट्रंप ने चीन पर फोड़ा टैरिफ बम, तबाह हो रहा पाकिस्तान

वाशिंगटन। अमेरिका ने चीन पर ज्यादा टैक्स (टैरिफ) लगाने का फैसला लिया है. इसका असर अब सिर्फ चीन पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर भी दिखने लगा है. हैरान करने वाली बात ये है कि पाकिस्तान के शेयर बाजार में चीन से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी 29% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है, लेकिन फिलहाल इस पर 90 दिन की रोक लगाई गई है. इसके बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर असर पड़ा है. चीन की स्टॉक मार्केट जो टैरिफ लागू होने से पहले अच्छी चाल दिखा रही थी, अब धीमी पड़ गई है. शुक्रवार को शंघाई स्टॉक इंडेक्स में सिर्फ 14 अंकों की हल्की बढ़त देखी गई. पिछले 5 दिनों में इसमें 3 से 4 फीसदी तक की गिरावट आई है. साल की शुरुआत से अब तक इसका YTD रिटर्न -3.39% रहा है. पिछले साल इस इंडेक्स ने 52 हफ्तों का हाई 3,674.40 छुआ था, लेकिन अब यह 2,689.70 तक गिर चुका है.

पाकिस्तानी मार्केट में गिरावट

चीन पर अमेरिकी टैरिफ और पाकिस्तान पर 29% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने के बाद सोमवार को पाकिस्तानी मार्केट में इतनी गिरावट आई कि ट्रेडिंग ही रोकनी पड़ी. बुधवार को भी KEC-100 2,640.95 अंक या 2.29% की तगड़ी गिरावट के साथ 112,891.48 पर आ गया. शुक्रवार को भी PSK में बेचैनी देखने को मिली.

यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर रूस ने दागी मिसाइल

कीव। भारत में यूक्रेनी दूतावास ने कहा कि शनिवार को यूक्रेन में एक भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर रूसी मिसाइल ने हमला किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एंबेसी ने आरोप लगाया कि रूस भारत के साथ विशेष मित्रता का दावा करता है, लेकिन वह जानबूझकर यूक्रेन में भारतीय व्यवसायों को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी दूतावास ने लिखा, 'आज, यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम के गोदाम पर रूसी मिसाइल ने हमला किया। भारत के साथ विशेष मित्रता का दावा करते हुए मॉस्को जानबूझकर भारतीय व्यवसायों को निशाना बना रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बनाई गई दवाओं को नष्ट कर रहा है।' इससे पहले यूक्रेन में ब्रिटेन के राजदूत मार्टिन हैरिस ने दावा किया था कि रूसी हमलों ने कीव में एक प्रमुख दवा गोदाम को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमला रूसी ड्रोन द्वारा किया गया था।

दिल्ली को मिली पहली हार

दिल्ली। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रनों से हरा दिया है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 205 रन बनाए थे. जवाब में दिल्ली की पूरी टीम 193 रन ही बना पाई. यह दिल्ली की IPL 2025 में पहली हार है, इससे पहले उसने लगातार 4 जीत दर्ज की थीं. दूसरी ओर मुंबई को इस मैच में हार मिलती तो उसकी प्लेऑफ की राह मुश्किल हो जाती. 19वें ओवर में मुंबई इंडियंस के फील्डरों ने अजीबोगरीब अंदाज में रन-आउट की हैट्रिक लगाते हुए बाजी मारी.

206 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दीपक चाहर ने MI को जबरदस्त शुरुआत दिलाई. उन्होंने पारी की पहली ही गेंद पर जेक फ्रेजर मैकगर्क को चलता किया. उसके बाद अभिषेक पोरेल और करुण नायर ने मुंबई की गेंदबाजी की कमर तोड़ कर रख दी. दोनों ने मिलकर 61 गेंदों में 119 रन जोड़ डाले. पोरेल 33 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन करुण नायर अलग ही मूड में बैटिंग करने आए थे. नायर 89 रनों की तूफानी पारी खेल आउट हुए तब दिल्ली को 50 गेंदों में जीत के लिए 71 रन बनाने थे, यह देखने में बेहद आसान लक्ष्य नजर आने लगा था.

आखिरी 8 ओवरों में पलट गया पूरा मैच

12 ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए थे. टीम को जीत के लिए 48 गेंद में 66 रन बनाने थे. यहां से सूर्यकुमार यादव, ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल समेत अन्य बल्लेबाजों ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए. उसके अगले चार ओवरों में दिल्ली की टीम सिर्फ 24 रन बना पाई और तीन अहम विकेट गंवा दिए. इससे 16 ओवर तक स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए थे. एक समय जहां दिल्ली कैपिटल्स आसान जीत की ओर बढ़ रही थी, वहां आलम यह था कि 2 ओवरों में उसे 23 रन बनाने थे. चूंकि जसप्रीत बुमराह का एक ओवर बाकी था, इसलिए ये 23 रन भी पहाड़ से लक्ष्य की तरह प्रतीत हो रहे थे. 19वें यानी जसप्रीत बुमराह की पहली 2 गेंदों पर 8 रन आ चुके थे, लेकिन कौन जानता था कि उस ओवर की अगली तीन गेंदों पर दिल्ली के बाकी तीनों बल्लेबाज रन आउट हो जाएंगे.

राजस्थान को हरा टॉप-3 में पहुंची आरसीबी

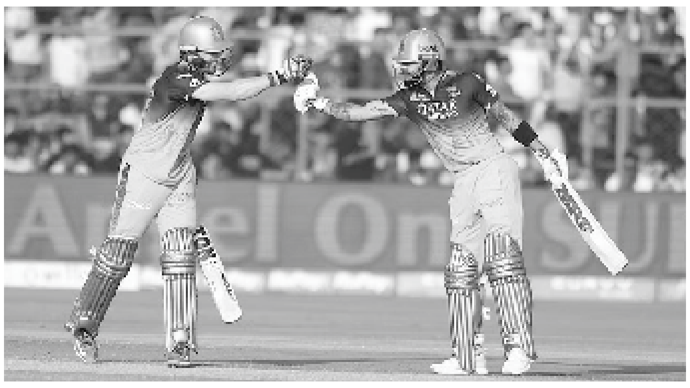

जयपुर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने विराट कोहली और फिल सॉल्ट के अर्धशतकों की मदद से राजस्थान रॉयल्स को नौ विकेट से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 173 रन बनाए थे। जवाब में आरसीबी ने 17.3 ओवर में एक विकेट पर 175 रन बनाकर मैच जीत लिया। आरसीबी के लिए सॉल्ट ने 33 गेंदों पर पांच चौकों और छह छक्कों की मदद से 65 रन बनाए, जबकि कोहली 45 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्कों के सहारे 62 रन बनाकर नाबाद लौटे। इनके अलावा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे देवदत्त पडिक्कल ने 28 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 40 रन बनाए।

आरसीबी इस मुकाबले में हरी जर्सी पहनकर उतरी थी। यह टीम हर सीजन कम से कम एक मैच हरी जर्सी में खेलती है। दरअसल, बेंगलुरु की टीम पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए हरे रंग की जर्सी पहनकर खेलती है। आरसीबी के लिए ग्रीन जर्सी में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन राजस्थान के खिलाफ वह जीत दर्ज करने में सफल रही। आरसीबी की ग्रीन जर्सी में यह पांचवीं जीत है। उसने ग्रीन जर्सी पहनते हुए दो बार राजस्थान को हराया है। आरसीबी की जीत से अंक तालिका में बदलाव हुआ है और गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम पांचवें स्थान पर खिसक गई है। आरसीबी छह मैचों में चार जीत और दो हार के साथ आठ अंक लेकर तीसरे स्थान पर आ गई है, जबकि राजस्थान ने भी छह मैच खेले हैं और वह दो जीत, चार हार के साथ चार अंक लेकर सातवें स्थान पर आ गई है।

अगले हफ्ते 1 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी सोने की कीमत

मुंबई। भारत में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के चलते लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने का रूख कर रहे हैं. इसी बीच, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93,000 रुपये के लेवल को पार कर गई है. अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी ट्रेड वॉर के चलते पैदा हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति, केंद्रीय बैंक की सोने की खरीद और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों की वजह से सोने की कीमतें बढ़ रही हैं. इन्हीं सबके बीच अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या 2025 में 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी? बिजनेसटुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, स्प्रोट एसेट मैनेजमेंट के वरिष्ठ पोर्टफोलियो मैनेजर रयान मैकइंटायर का कहना है कि केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद और विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रामक टैरिफ पॉलिसी की वजह से सोने को मजबूती मिल रही है. 2025 में अमेरिकी फेड द्वारा दो बार ब्याज दरों में कटौती किए जाने की उम्मीद है, इसके चलते सोना 1 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है.

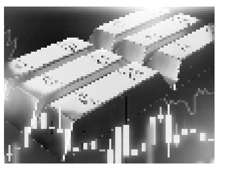

UPI डाउन से करोड़ों लोग प्रभावित! कहीं आपका भी तो पैसा नहीं अटका...

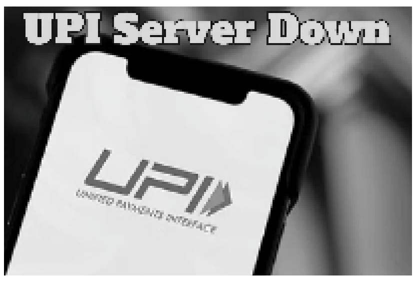

मुंबई। देशभर में UPI पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए शनिवार, 12 अप्रैल 2025 के दिन की शुरुआत परेशानियों से हुई. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में आए एक बड़े टेक्निकल आउटेज ने PhonePe और Google Pay जैसे पॉपुलर ऐप्स को घंटों के लिए ठप कर दिया. इस वजह से लोगों को रोजमर्रा की खरीदारी, बिल पेमेंट और पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

UPI सिस्टम ठप क्यों हुआ?

UPI सिस्टम 24 घंटे, 365 दिन, बिना किसी छुट्टी के चलता है. भारत में हर महीने 17 अरब से ज्यादा ट्रांजेक्शन और 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान UPI के ज़रिए होता है. दुनिया के 630 से ज़्यादा बैंक इस सिस्टम से जुड़े हैं, और अब तो नेपाल, यूएई, फ्रांस, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस और श्रीलंका जैसे देशों में भी यूपीआई काम कर रहा है.देश में डिजिटल पेमेंट्स का 83 फीसदी हिस्सा सिर्फ यूपीआई के ज़रिए होता है. ऐसे में यह आउटेज एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब सरकार डिजिटल इंडिया को वैश्विक स्तर पर प्रमोट कर रही है.

NPCI ने क्या कहा?

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई आउटेज पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है. NPCI ने कहा है, "यूपीआई सिस्टम में फिलहाल कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से कुछ ट्रांजेक्शन फेल हो रहे हैं. हमारी टेक्निकल टीम इस समस्या को ठीक करने में लगी हुई है. हम जल्द ही इसे पूरी तरह से ठीक कर लेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे. इस परेशानी के लिए हमें खेद है."

अब चीन नहीं भारत बन रहा Apple का हब!

मुंबई। एप्पल इंक ने बीते 12 महीनों में भारत में 22 बिलियन डॉलर वैल्यू के आईफोन का निर्माण किया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 60 परसेंट ज्यादा है. इस मामले से परिचित लोगों का कहना है कि आज के समय में 20 परसेंट आईफोन या पांच में से एक आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अब इस दक्षिण एशियाई देश में होती है. इससे पता चलता है कि एप्पल और उसके सप्लायर्स अब चीन से बाहर भारत का रूख कर रहे हैं. ट्रेड वॉर के इस बढ़ते खतरे के बीच एप्पल चीन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर जोर दे रहा है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत के 26 परसेंट टैरिफ के मुकाबले चीन पर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ 145 परसेंट है. बताया जा रहा है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के चलते ही भारत से अमेरिका को आईफोन की शिपमेंट में तेजी आई है.इस प्रक्रिया की शुरुआत कोरोना महामारी के समय में हुई थी, जब 'जीरो कोविड नीति' के चलते कुछ फैक्ट्रियों का कामकाज प्रभावित होने के बाद एप्पल ने चीन से भारत का रूख किया.

अमेरिकी टैरिफ से वैश्विक व्यापार में होगी तीन प्रतिशत की कमी, लेकिन भारत को होगा लाभ

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की एक शीर्ष अर्थशास्त्री ने कहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के कारण वैश्विक व्यापार में तीन प्रतिशत की कमी आ सकती है। इससे अमेरिका और चीन जैसे बाजारों से निर्यात घट सकता है और इसकी जगह भारत, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों को लाभ हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र की कार्यकारी निदेशक पामेला कोक-हैमिल्टन ने शुक्रवार को जिनेवा में कहा कि व्यापार के तौर-तरीके और आर्थिक एकीकरण में दीर्घकालिक बदलावों के साथ वैश्विक व्यापार में तीन प्रतिशत की कमी आ सकती है।

उदाहरण के लिए मेक्सिको से निर्यात अत्यधिक प्रभावित हुआ है। अब यह अमेरिका, चीन, यूरोप और यहां तक कि अन्य लातिन अमेरिकी देशों जैसे बाजारों से स्थानांतरित हो रहा है। इससे कनाडा, ब्राजील और कुछ हद तक भारत को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार वियतनामी निर्यात अमेरिका, मेक्सिको और चीन से हट रहा है, जबकि पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और अन्य बाजारों की ओर काफी बढ़ रहा है।

परिधान का उदाहरण देते हुए कोक-हैमिल्टन ने कहा कि विकासशील देशों के लिए आर्थिक गतिविधि और रोजगार के मामले में कपड़ा उद्योग शीर्ष पर है। अगर टैरिफ लागू होता है तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े परिधान निर्यातक बांग्लादेश को 37 प्रतिशत का जवाबी शुल्क झेलना पड़ेगा। इससे 2029 तक अमेरिका को होने वाले वार्षिक निर्यात में 3.3 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।

स्मार्टफोन, लैपटाप को अमेरिका ने टैरिफ से बाहर किया

। ट्रंप प्रशासन ने स्मार्टफोन, लैपटाप और कंप्यूटर समेत कई अन्य इलेक्ट्रानिक सामान को पारस्परिक टैरिफ से बाहर रखने की घोषणा की है। इस कदम से अमेरिका से बाहर बनने वाली लोकप्रिय उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी।

आयुष्मान भारत योजना : भुगतान में देरी से इलाज पर संकट

देहरादून। उत्तराखंड सरकार के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी गोल्डन कार्ड की विश्वसनीयता बनाए रखना बड़ी चुनौती बनती जा रही है. सरकारी व निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत इलाज की सुविधा तो जारी है, लेकिन राज्य सरकार पर बढ़ते वित्तीय दबाव के चलते कई अस्पताल अब इस योजना के तहत मरीजों का इलाज करने से पीछे हट रहे हैं. पिछले एक वर्ष में राज्य के अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 300 करोड़ रुपये का इलाज किया है, जबकि सरकार अब तक केवल 120 करोड़ रुपये ही जारी कर पाई है. शेष 180 करोड़ रुपये का भुगतान लटकने के कारण अस्पतालों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और उनका कहना है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे इस योजना के मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे. राज्य के 1,28,761 सेवा प्रदाताओं में से 91,390 पंजीकृत अस्पतालों, फार्मेसियों व लैब्स ने सेवा दी है, लेकिन भुगतान में देरी के चलते उनमें असंतोष व्याप्त है. अस्पतालों का कहना है कि इलाज के बदले जो खर्च किया जा रहा है, उसका भुगतान समय पर नहीं मिल रहा.

केंद्र से मिलने वाले बजट में आई कमी

राज्य सरकार को केंद्र से मिलने वाले बजट में भी कमी आई है. योजना के तहत अब तक कुल 510 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जबकि इसके अनुपात में अनुदान पर्याप्त नहीं मिल पा रहा. यही वजह है कि राज्य सरकार के सामने बजटीय संकट खड़ा हो गया है। राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य दिलीप जावलकर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हो रही दिक्कतों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उनका कहना है कि अस्पतालों का बकाया भुगतान जल्द किया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों, इसके लिए उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है.

सुशासन तिहार : पहले चरण के अंतिम दिन ग्रामीणों संग जमीन में बैठे अफसर

ग्रामीणों की दिक्कतों और लंबित समस्याओं के लिए विष्णुदेव सरकार के नौकरशाह कर रहे गांव-गांव संवाद

शहर सत्ता/रायपुर। विष्णुदेव साय के सुशासन में ऐसी केबिन से निकलकर ग्रामीणों की समस्याओं के लिए कलेक्टर और सीईओ जमीन पर बैठकर ग्रामवासियों से आवेदन ले रहे हैं।

साय के सुशासन का ही नतीजा है कि कलेक्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष ने खैरबनाकला पहुंचकर जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।

कल प्रथम चरण के अंतिम दिन कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू बोड़ला विकासखंड के ग्राम खैरबनाकला में पहुंचकर स्वयं ग्रामवासियों से आवेदन लिये।

उन्होंने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान ग्रामवासियों से चर्चा कर उनकी शिकायत, समस्या और मांगों को सुनकर आवेदन लिया। उन्होंने सुशासन तिहार की अवधारणा, उद्देश्य एवं गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अजय कुमार त्रिपाठी, अपर कलेक्टर मुकेश रावटे, बोड़ला एसडीएम सुश्री रूचि शार्दुल, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

ऐसे होगा समस्याओं का निदान

- समस्या, शिकायत और मांगों को लेकर सुबह 10 बजे से शाम 05 बजे तक समाधान पेटी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया।
- पहले चरण में आम जनता से आवेदन प्राप्त किया गया। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण होगा।
- तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
- प्रत्येक 08 से 15 पंचायतों के मध्य शिविर लगेंगे, जहां आवेदकों को उनके प्रकरणों की जानकारी दी जाएगी।
- शिविरों की तिथि की सूचना एसएमएस और पावती के माध्यम से दी जाएगी।

अवैध शराब मामला: पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

बिलासपुर। अवैध शराब जब्ती के एक मामले में पुलिस की जब्ती और दस्तावेजी कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा है। पुलिस ने आरोपी बताते हुए मामला दर्ज कर निचली अदालत में पेश

किया। मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए सजा भी सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाई कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। धमतरी जिले के मगरलोड पुलिस ने याचिकाकर्ता अर्जुन देवांगन के खिलाफ अवैध शराब बिक्री का मामला दर्ज किया था। 40 क्वार्टर देशी शराब (180 मि.ली. प्रति बोतल) को अवैध रूप से मोटरसाइकिल में ले जाने का पुलिस ने उस पर आरोप लगाते हुए मौके से शराब जब्त करना बताया और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया था।

झारखंड से जुड़ना हुआ आसान : कन्हर नदी पर बन रहे पुल का नेताम ने किया निरीक्षण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के नेतृत्व में शासन ने सीमावर्ती इलाकों के विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड में कन्हर नदी पर बन रहे उच्चस्तरीय पुल का आज राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम ने स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। यह पुल न केवल सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ेगा, बल्कि दो राज्यों के बीच सड़क सम्पर्क का मुख्य माध्यम बनेगा।

गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री नेताम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना को तय समयसीमा में पूरा किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि यह पुल क्षेत्रीय समेकित विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पुल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा संस्थान और बाजार अब ग्रामीणों की पहुंच में होंगे। इसके अलावा पर्यटन और स्थानीय व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा।

60 प्रतिशत कार्य पूर्ण, जून तक पुल होगा तैयार

लोक निर्माण विभाग द्वारा 15.20 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह पुल 312 मीटर लंबा और 8.4 मीटर चौड़ा है। अब तक 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। 12 पियर और 2 अबटमेंट में से अधिकांश का निर्माण पूरा हो गया है और स्लैब कार्य भी तेजी से प्रगति पर है। जून 2025 तक पुल का निर्माण पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। इस पुल से धौली, झारा, कुशफर, सेमरवा, पचावल, आनंदपुर जैसे 20 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। बरसात के समय जब नदी उफान पर होती है, तब लोगों को इलाज, शिक्षा और बाजार तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। पुल बन जाने के बाद यह समस्या इतिहास बन जाएगी।

अनुराग सिंह देव बने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष

रायपुर। अनुराग सिंह देव ने अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का पदभार माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं अन्य सम्माननीय विशिष्ठ अतिथियों की उपस्थिति में ग्रहण किया ।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव द्वारा 12.04.2025 को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का पदभार ग्रहण किया जिसमें मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, आवास एवं पर्यावरण, वित्त मंत्री, ओ.पी. चौधरी, मंत्री राम विचार नेताम, सांसदों, विधायकों एवं निगम/मण्डल/आयोग के अध्यक्षगण, नगर निगम के माननीय महापौर, वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं अन्य सम्माननीय जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के पदभार ग्रहण के अवसर पर अध्यक्ष अनुराग सिंह देव को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि स्वयं का एक आवास हो, सर पर छत हो। इसी परिकल्पना को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी को आवास देने हेतु घोषणा की गई है।

डिप्टी सीएम साव ने एक्शन-प्लान बनाने दिए निर्देश

- दूषित पानी सप्लाई पर सीएमओ और प्रभारी को नोटिस

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित नीर भवन में आयोजित बैठक नगरीय निकायों में प्रगतिरत एवं अपूर्ण कार्यों को एक्शन-प्लान बनाकर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों तथा अटल परिसरों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री आर. एक्का भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा कि हमें शहरों की सूरत एवं सीरत को बदलना है। नगरीय प्रशासन की व्यवस्था व्यवस्थित शहर के मापदंडों के अनुरूप हो, इसके लिए हमें आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। नगरीय प्रशासन की टीम अच्छा काम करेगी, तो कार्यों का क्रियान्वयन भी धरातल पर दिखेगा। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप शहरों के विकास में अपने अनुभव का पूरा उपयोग करें। आपके अनुभव का पूरा लाभ शहरवासियों को मिलना चाहिए। विभाग का काम एक मिसाल के तौर पर स्थापित हो, यह मेरी आप लोगों से अपेक्षा है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में जारी घोषणा पत्र, निकायों के कामकाज तथा विधानसभा में दिए गए आश्वासनों पर विभागीय कार्यवाही की समीक्षा की।

उन्होंने विभिन्न नगरीय निकायों में अपूर्ण और लंबित कार्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए इन कार्यों की पूर्णता की समय-सीमा तयकर एक्शन प्लान बनाकर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव ने अटल परिसरों के निर्माण की असंतोषजनक प्रगति पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसमें विलंब करने वाले निकायों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री साव ने विधानसभा में प्रस्तुत सीएजी (CAG) रिपोर्ट एवं उनकी अनुशंसा के अनुसार यथोचित कार्यवाही करने को कहा।

रायपुर एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी इंटरनेशनल कार्गो की सुविधा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नवा रायपुर के सेक्टर-24 में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्षों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर एवं छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कुमार चंद्रवंशी को नए दायित्व के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद की किसानों एवं कृषि के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। खेत तभी लहलहाते हैं जब बीज अच्छा होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज समय पर उपलब्ध हों।

सुशासन की लंबी छलांग

नवा रायपुर में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट

शहर सत्ता/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पोलीमैटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी। यह कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ में 1,143 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। डेढ़ लाख वर्ग फीट में बनने वाला यह प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेगा, जिनका उपयोग टेलीकॉम, 6जी/7जी, लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा। इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि छत्तीसगढ़ में पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना का भूमिपूजन हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में सेमीकंडक्टर उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से कंपनी को यहां निवेश में सफलता मिलेगी। अब 6जी और 7जी तकनीक भी आ रही है और मुझे खुशी है कि इनके लिए आवश्यक चिप्स हमारे देश में ही तैयार होंगे, और नवा रायपुर, अटल नगर में हमारे इंजीनियर इन्हें बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष दिसंबर में दिल्ली में आयोजित एक इंवेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम में राज्य के अधिकारियों की मुलाकात पोलीमैटेक के प्रबंधन से हुई थी और उसी समय कंपनी ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताई थी।

- **एनआरडीए ने 45 दिनों के भीतर सेक्टर-5 में डेढ़ लाख वर्ग फीट भूमि का किया आबंटन**
- **1,143 करोड़ रुपए की लागत से संयंत्र होगा स्थापित, मिलेगा रोजगार**

उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में उद्योग विभाग और एनआरडीए ने कंपनी के लिए नवा रायपुर के सेक्टर-5 में डेढ़ लाख वर्ग फीट भूमि उपलब्ध कराई। एनआरडीए ने 45 दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर भूमि आबंटित की और 25 दिनों से कम समय में लीज डीड पंजीकरण का कार्य भी संपन्न हुआ।

रायपुर प्रेस क्लब : अध्ययनशील पत्रकारों को गोविंद लाल वोरा लाइब्रेरी समर्पित

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की किताबों के लिए 1 लाख रुपये देने की घोषणा

शहर सत्ता/रायपुर। तत्कालीन मध्य प्रदेश के दूसरे और छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे पहले प्रेस क्लब रायपुर प्रेस क्लब में स्वर्गीय गोविंद लाल वोरा लाइब्रेरी का शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश त्रिवेदी की गौरवमयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस क्लब लाइब्रेरी में किताबों के लिए स्वनिधि से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि 30 दिन के भीतर किताबों के लिए राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। स्व गोविंद लाल वोरा को याद करते हुए डॉ. रमन सिंह ने उनकी शालीनता और जीवन पर्यंत पत्रकारिता करते रहने की बातें साझा की। उन्होंने कहा, मेरे मुख्यमंत्री रहते और उससे पहले भी कभी भी वोरा जी ने मुझसे किसी काम के लिए नहीं कहा। उन्होंने याद करते बताया कि मजाक में वे वोरा जी को संपादकों का देवानंद कहते थे।

इस मौके पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने किताबों और पढ़ने-लिखने के महत्व के अनुभव साझा किए, राजनांदगांव की लाइब्रेरी में किताब पढ़ने की शुरुआत के प्रसंग साझा करते हुए, उन्होंने पत्रकारों को पढ़ने-लिखने के लिए प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार उमेश त्रिवेदी ने कहा, भले ही वे मध्यप्रदेश से हैं, लेकिन दोनों प्रदेशों में पत्रकारिता का डीएनए एक ही रहा है। उन्होंने रायपुर प्रेस क्लब के प्रयासों की तारीफ की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक श्री अरुण वोरा ने भी लाइब्रेरी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और प्रेस क्लब के प्रयासों की सराहना की।

रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने आगामी दिनों में प्रेस क्लब में वीडियो प्रोडक्शन स्टूडियो, फोटो गैलरी बनाने के योजना साझा की। साथ ही पत्रकारों से, विशेषकर नए पत्रकारों से आग्रह किया कि वे रायपुर प्रेस क्लब की लाइब्रेरी का सदुपयोग करें।

नक्सली कमाण्डर समेत तीन ढेर, हथियार भी बरामद

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जवानों ने अम्बेली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड माटवाड़ा एलओएस कमाण्डर एसीएम अनिल पूनेम समेत तीन मओवादियों को ढेर कर दिया है। साथ ही मौके से 3 नग 12 बोर रायफल, सिंग्ल शा ॅट रायफल समेत विस्फोटक व नक्सली सामग्री जब्त की है। दरअसल, बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र के जंगल में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ व कोबरा 210, 202 की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इस दौरान आज सुबह 9 बजे सुरक्षा बलों व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। दोनां तरफ से चली गोलीबारी में अम्बेली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माटवाड़ा एलओएस कमाण्डर एसीएम अनिल पूनेम मारा गया। मारे गये माओवादी पर 5 लाख का इनाम घोषित था। वहीं, मारे गये अन्य दो माओवादियों की पहचान की जा रही है। आईजी बस्तर रेंज सुन्दरराज पी.ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त टीम निकली थी। अभियान के दौरान सुरक्षा बलो की कार्यवाही में 3 हार्ड कोर माओवादियों को सुरक्षा बलो ने मार गिरया गया।

रायपुर का 'नेट एनर्जी प्लस' CSERC भवन

क्रेडा की महती भूमिका से विश्वकर्मा अवार्ड के लिए चयनित

शहर सत्ता/रायपुर। स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) नेट एनर्जी प्लस भवन को '16 वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2025' के लिए चयनित किया गया है। इस भवन की निर्माण परिकल्पना और परामर्ष सेवाए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ¼CREDA) द्वारा प्रदान की गईं है एवं छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने इस भवन का निर्माण किया है। CREDA ने इस भवन को ऊर्जा-दक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके फलस्वरूप यह भवन भारत की पहली नेट एनर्जी प्लस बिल्डिंग के रूप में विकसित हुई है।

ऊर्जा-दक्ष भवन निर्माण को बढ़ावा देने प्रतिबद्ध

CREDA के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश सिंह राणा ने कहा: CSERC नेट एनर्जी प्लस भवन देश के बिल्डींग क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण का एक मिशाल बनी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में भविष्य में निर्माण होने वाली भवनों को ऊर्जा दक्ष भवन संहिता अंतर्गत नेट एनर्जी प्लस आधारित भवन के रूप निर्माण किया जायेगा। CREDA हमेशा से अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा-दक्ष भवन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। CSERC भवन, नेट जीरो ऊर्जा अवधारणा को अपनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए इसका चयन छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। CSERC भवन को CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2025 के लिए चयन होना छत्तीसगढ़ को सतत विकास और ऊर्जा-दक्ष भवन निर्माण की दिशा में राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा।

CREDA की अहम भूमिका

CREDA द्वारा CSERC भवन के निर्माण की दिशा में नेट एनर्जी प्लस की परिकल्पना, डिजाईनिंग एवं इंजिनियरिंग सेवाएं दी गई है। इस भवन में सौर ऊर्जा का समायोजन के तकनीक को क्रेडा द्वारा विकसित किया गया है, तथा भवन को Passive Design के आधार पर निर्माण करने हेतु लेआऊट तैयार किया गया है। भवन में प्राकृतिक वेंटिलेषन के साथ-साथ ऊर्जा एवं जल संरक्षण उपायों को पर्यावरण अनुकूल सम्मिलित किया गया है। इस भवन को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटेड भवन के रूप में प्रमाणित किया गया है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

फिल्म विकास निगम पर पद्मश्री प्राप्त हीरो MLA बनते ही.. "खामोश"

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की बात हो या फिल्म विकास निगम के गठन की माँग – एक वक्त था जब अनुज शर्मा इस मोर्चे पर सबसे आगे खड़े नजर आते थे। कलाकार से जनप्रतिनिधि(विधायक)बनने तक के उनके सफर में उम्मीदें भी साथ चली थीं कि अब इंडस्ट्री को एक मज़बूत आवाज मिलेगी।

लेकिन अफसोस, अब जब उनके पास असली ताकत है – एक विधायक के रूप में – तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा की आवाज़ कहीं खो सी गई है। न तो फिल्म नीति पर ठोस काम हो रहा है, न ही फिल्म सिटी की दिशा में कोई प्रगति। कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने का वादा अब महज़ कागज़ों तक सीमित है। हाँ, एक बात ज़रूर हुई – उनकी आने वाली फिल्म "सुहाग" का ट्रेलर मुख्यमंत्री से लॉन्च करवा लिया गया। ये उपलब्धि है या अवसरवाद, इस पर चर्चा ज़रूरी है।

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े युवा कलाकार और निर्माता सवाल उठा रहे हैं – क्या अब जनप्रतिनिधि बनने के बाद अनुज शर्मा का फोकस सिर्फ़ अपनी फिल्मों तक सिमट गया है? क्या अब उनकी प्राथमिकता व्यक्तिगत प्रमोशन है या छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री का समग्र विकास? अब देखना यह है कि क्या अनुज शर्मा एक बार फिर वही पुरानी ऊर्जा के साथ लौटेंगे जो कभी निगम के लिए

राजू दीवान: पोस्टर चिपकाने से नेशनल अवॉर्ड तक का सफर

कभी सिनेमा हॉल की दीवारों पर खुद अपने हाथों से पोस्टर चिपकाने वाला एक कलाकार—आज उसी कलाकार को देश का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सच्ची कहानी है राजू दीवान की, जो अब सोशल मीडिया के माध्यम से नए युग की सिनेमा क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं।एक समय था जब न यूट्यूब था, न इंस्टाग्राम। फिल्मों का प्रचार करना मतलब था – सड़कों पर पोस्टर चिपकाना, नुक्कड़-नाटक करना या छोटे-बड़े बैनर लगवाना। राजू दीवान ने शुरुआत की थी वीडियो एल्बम से। कड़ी मेहनत, सीमित संसाधनों और बिना किसी गॉडफादर के वे धीरे-धीरे फिल्मों तक पहुंचे। दर्जनों फिल्में कीं, लेकिन प्रचार की कमी के चलते वे लोगों तक पूरी तरह पहुँच नहीं पाईं।

और फिर आई 'निम्मो' – जिसने सब कुछ बदल दिया

साल 2021 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई – 'निम्मो'। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक सामाजिक संदेश था, एक नई सोच की दस्तक थी। इस फिल्म ने 'शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल लीगल 2021' में 700 फिल्मों को पछाड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता। इस सम्मान को देश के चीफ जस्टिस के हाथों हासिल करना किसी सपने से कम नहीं था।

अब सोशल मीडिया बना राजू दीवान का नया मंच

अब राजू दीवान पारंपरिक सिनेमा से आगे बढ़कर सोशल मीडिया पर पूरी रफ्तार से सक्रिय हैं। वे न केवल सामाजिक संदेश देने वाली फिल्में बना रहे हैं, बल्कि कॉमेडी और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट भी रच रहे हैं – और ये सब कुछ सुंदरानी यूट्यूब चैनल पर।

जल्द आ रही हैं दो नई फिल्में

अप्रैल के मध्य तक उनकी दो नई फिल्में रिलीज़ होने जा रही हैं, जिनका निर्देशन और लेखन दोनों उन्होंने स्वयं किया है। ये फिल्में होंगी – मनोरंजन से भरपूर, लेकिन एक सार्थक संदेश के साथ।

राजू दीवान की कहानी एक मिसाल है उन सबके लिए जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ा सपना देखते हैं। वे बताते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का ज़रिया नहीं, बल्कि क्रांति का मंच भी बन सकता है बस आपके पास कहने को कुछ हो और दिखाने की हिम्मत हो।

शहरसत्ता के कला समीक्षक पूरन किरी की प्रस्तुति

छॉलीवुड को नया विजन देने वाले हैं निर्देशक हेमंत तिवारी

खरखरा से कैमरे तक: हेमंत तिवारी (राहुल) की छत्तीसगढ़ी सिनेमा में नई उड़ान – 'मोह अऊ माया' और 'पायलीखंड' से करेंगी दस्तक

रायपुर/छुरा। छत्तीसगढ़ की माटी से एक नई प्रतिभा उभर रहा है। नाम है हेमंत तिवारी, जिसे सब प्यार से राहुल कहते हैं। गरियाबंद जिले के छोटे से गांव खरखरा में बचपन से सपना संजोय कि एक दिन वो बड़ी स्क्रीन में अपने काम से जाने जायेंगे। बचपन में देखे सपनों को हकीकत में बदलने वाले राहुल ने खुद को कैमरा, एडिटिंग और डायरेक्शन की दुनिया में न सिर्फ साबित किया, बल्कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया विजन भी दिया।

13 साल से सीजी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय राहुल ने अब तक 50 से अधिक एल्बम सॉन्ग, 100+ अवेयरनेस शॉर्ट फिल्में और कई सरकारी विज्ञापन डायरेक्ट किए हैं। वो एक ऑलराउंडर हैं – कभी डायरेक्टर, तो कभी कैमरा मैन या एडिटर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन उनका असली जुनून है – डायरेक्शन।

जब राहुल गांव से रायपुर आए, तब न सोशल मीडिया था, न कोई गाइड। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो दूसरों की शूटिंग देखने जाते, वहीं से सीखते, फिर खुद से शॉर्ट फिल्में बनानी शुरू कर दीं। उन्होंने IAS-IPS अधिकारियों के लिए भी प्रेरणादायक शॉर्ट फिल्में बनाईं। उनका मानना है कि "डायरेक्टर का सर्वगुणी होना जरूरी है, तभी सच्ची कहानी बनती है।"

हेमंत तिवारी का मानना है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को छोड़े बिना भी फिल्मों में नयापन लाया जा सकता है। वो कहते हैं, "बासी चिला और चटनी की अपनी अलग पहचान है, बस उसमें थोड़ा भाजी, पापड़, सलाद जोड़ दो – स्वाद दोगुना हो जाता है। फिल्मों में भी वही ज़रूरी है।"

आने वाली छत्तीसगढ़ी फिल्में

1. मोह अऊ माया (कमर्शियल फिल्म)
2. पायलीखंड (हीरा खदान पर आधारित फिल्म)

क्या राहुल बनेंगे CG सिनेमा के नए निर्देशक स्टार?

छत्तीसगढ़ी सिनेमा को एक नई दिशा देने वाले हेमंत तिवारी (राहुल) अब अपनी फिल्मों के ज़रिए दर्शकों के दिलों में जगह बनाने को तैयार हैं। "मोह अऊ माया" और "पायलीखंड" सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ी सोच, संघर्ष और संस्कार की जीवंत कहानियां हैं। अब वक्त बताएगा – क्या गांव से निकला ये लड़का छत्तीसगढ़ी सिनेमा का अगला 'गेम चेंजर' बनेगा?

अमिय ठाकुर यानि ट्रिप्लॉइड मोटरसाइकिल के रियल लाइफ हीरोज

- छत्तीसगढ़ के राइडर्स अब फिल्मी पर्दे पर भी दिखा रहे हैं दम
- ट्रिप्लॉइड मोटरसाइकिल क्लब बना रियल लाइफ हीरोज का ग्रुप

शहर सत्ता/रायपुर। जब जुनून रफ्तार से टकराता है, तो कहानी बनती है ट्रिप्लॉइड मोटरसाइकिल क्लब की। रायपुर में स्थापित इस क्लब के संस्थापक अमिय ठाकुर हैं, और आज यह क्लब 60 से अधिक राइडर्स के साथ देशभर में अपनी पहचान बना चुका है। यह क्लब न केवल राइडिंग के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक और फिल्मी उद्देश्य भी छिपा है। क्लब के कई सदस्य आज फिल्मों में स्टंटमैन के रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ वे रियल बाइक स्टंट्स करते हुए दर्शकों को रोमांचित कर रहे हैं।

महिला राइडर्स और फिल्मी कनेक्शन

क्लब की खास बात यह है कि इसमें महिला राइडर्स भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं, जो ना केवल समाज में नई सोच ला रही हैं, बल्कि एक्शन और साहस का प्रतीक भी बन रही हैं। आज ट्रिप्लॉइड क्लब छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक ऐसा मंच बन चुका है जो सुरक्षित राइडिंग, फिल्मी स्टंट्स, पर्यटन में स्वच्छता, और सामाजिक जिम्मेदारी – इन सभी को जोड़कर एक नई मिसाल पेश कर रहा है। तो अगली बार जब किसी फिल्म में दमदार बाइक स्टंट देखें – तो याद रखिए, वो राइडर शायद ट्रिप्लॉइड से हो... और वो सिर्फ स्टंट नहीं कर रहा, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान भी बढ़ा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

क्लब ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व इंडिया बाइक वीक जैसे बड़े मंच पर किया, जिसे रायपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके अलावा क्लब ने राज्य का सबसे बड़ा बाइक मीट-अप आयोजित किया, जो कि चाय पकौड़ा राइड के रूप में पहली बार छत्तीसगढ़ में लाया गया। इसमें करीब 350 राइडर्स शामिल हुए थे।

पर्यटन और स्वच्छता को बढ़ावा देना

ट्रिप्लॉइड मोटरसाइकिल क्लब का मूल उद्देश्य है – पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखना और स्वच्छ व जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना। क्लब के हर व्लॉग, वीडियो और राइड में यह साफ दिखाई देता है कि वे जहां भी जाते हैं, वहाँ न सिर्फ सफाई का ध्यान रखते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को भी इसके लिए जागरूक करते हैं।

बाबा साहेब कहा करते थे- "शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है, जो पियेगा वो दहाड़ेगा"

14 अप्रैल भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर विशेष

ज्योत्सना मेश्राम, रायपुर

भारतीय संविधान के शिल्पी डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ा एक रोचक प्रसंग याद आता है जब एक बार विदेशी पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल भारत भ्रमण पर आया। यह प्रतिनिधि मंडल जब बाबा साहेब अंबेडकर के नई दिल्ली स्थित निवास पर पहुंचा तो उन्हें आधी रात में भी डॉ. अंबेडकर अपने अध्ययन कक्ष में पढ़ते हुए नजर आये। तब उन्होंने अंगरक्षकों से अंदर प्रवेश की इजाजत के साथ अपना परिचय देते हुए सवाल किया। जब हम अन्य राष्ट्रीय नेताओं के यहां मुलाकात करने उनके निवास पर गये तो वे सोते हुए मिले, मगर इतने रात भी आप जग रहे हैं, इसका क्या कारण है ? बाबा साहब ने कहा बंधुओं, वे इसलिए सोए हुए हैं क्योंकि उनका समाज जगा हुआ है ? उनका नेता सो जायेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो कौम, वे लोग, वह समाज पिछड़ा हुआ है उनका नेता सो जाएगा तो वह समाज कैसे आगे बढ़ेगा ?

बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म यद्यपि निर्धन तथा दलित परिवार में हुआ किंतु उन्होंने अपने कठोर परिश्रम, निरंतर संघर्ष और योग्यता से तत्कालीन विषम और कठिन सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद भी संविधान के निर्माता बनने तक के उच्च शिखर को प्राप्त किया। बाबा साहेब ने सतत् और कठिन परिश्रम से विद्यार्जन किया और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता बने। अपने ज्ञान से केवल वे ही आलोकित नहीं हुए बल्कि उन्होंने पूरे समाज को आलोकित किया। बाबा साहेब एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने मानवतावादी मूल्यों की स्थापना तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन जनमानस को समर्पित कर दिया। समाज में समरसता के पक्षधर बाबा साहेब ने उपेक्षित और निर्बल लोगों के जीवन में एक नयी चेतना का प्रकाश फैलाया। उनका मानना था कि समाज सुधार के बिना सच्ची राष्ट्रीयता का उदय संभव नहीं। बाबा साहेब ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उपेक्षित और शोषित वर्ग के दिलों में नयी स्फूर्ति और चेतना का संसार कर उसे आम जनता के बराबर खड़ा करने का प्रयास किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब संविधान निर्माण का कार्य डॉ. बाबा साहब अंबेडकर को सौंपा गया तो उन्होंने न्याय, समता और बंधुत्व के महान सिद्धांत पर आधारित विश्व के सर्वा◌ेत्तम संविधान के निर्माण में उल्लेखनीय भूमिका निभायी। यह संविधान हमें समानता और अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। बाबा साहेब के इस महान कार्य के लिए अमरीका की कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें एल.एल.डी. की मानद उपाधि से विभूषित किया।

संघर्ष व्यक्तित्व की कसौटी है उस कसौटी पर खरा उतरने वाला व्यक्ति यदि नैतिकता से पूरी तरह जुड़ा हुआ हो तो उसकी कभी पराजय नहीं होती। यदि पराजय होती भी है तो वह क्षणिक ही रहती है। डॉ. अंबेडकर का जीवन

प्रतिक्रिया से भरा है, आवेगों से सना रहा है। अंतर यह है कि उनकी प्रतिक्रिया और आवेग स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि उस दलित समाज के उद्धार के लिए थे। जिस पर सदियों से आघात होता रहा है। यदि राष्ट्र के लिए सब कुछ नहीं कर पाते जो उन्होंने कर दिया। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने दलितों के उद्धार में अपनी सारी जिंदगी की आहूति कर दी उन्होंने दकियानुसी तथाकथित सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के विरोध में तीखा संघर्ष किया और समुद्र मंथन जिससे उत्पीड़ित और समस्त जनता के लिए महासुखदायी अमृत हाथ लगा। जैसा कार्य किया उसकी मानसिकता बदली और जीवन को एक नया पाथेय मिला।

डॉ. भीमराव अंबेडकर एक ऐसा बहुमुखी व्यक्तित्व है, जिसके मूल में शोषितों उपेक्षितों को न्याय दिलाने की छटपटाहट है। इसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। अपने भाषण व लेखन के द्वारा जनता को सतत जागृत किया। संभवतः उनकी जीवनकाल में उनके कार्यों का ठीक-ठीकं आंकलन नहीं हो सका। उन्होंने स्वयं कहा था कि "लोग मुझे अभी समझ नहीं पाये हैं मुझे उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। एक समय आएगा जब इस देश के लोग मुझे ठीक प्रकार से समझ पाएंगे और सम्मान करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा समय आएगा तब तक मैं शायद जीवित नहीं रहूंगा।" उनका यह कथन सत्य सिद्ध हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि बाबा साहेब ने अपने जीवन और कार्यों से भारत के करोड़ों शोषितों और पीड़ित व्यक्तियों के जीवन में सोयी हुई जीवनी शक्ति को जागृत किया। डॉ. अंबेडकर अपनी मंजिले साथ लेकर ही चलते रहे, अदम्य साहस के साथ उनका त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनको अंपनी अस्पृश्यता का बोध तो उन्हें बचपन में ही हो गया था। विद्यार्थी जीवन में यह भान हुआ की दलितों की उन्नति का रामबाण उपाय है शिक्षा, अंबेडकर के जीवन का ध्येय अछूतों को न्याय और समानता दिलाना था उन्होंने दलितों के नेतृत्व का आरंभ 'मूकनायक' समाचार पत्र के प्रकाशन से किया।

अंबडेकर का कहाना था कि स्वतंत्रता भीख मांगकर नहीं मिलती, उसे अपनी शक्ति व सामर्थ्य से पाना होता है आत्मोद्धार किसी की कृपा से नहीं होता अपना उद्धार स्वयं करना होता है आत्मोद्धार के लिए अंबेडकर आगे आए बंबई विधान सभा के सदस्य बनकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया इस दौरान स्त्री मजदूरों को प्रसूति अवकाश देने के संबंध में विधेयक प्रस्तुत किया इसे उन्होंने राष्ट्रीय हित का कार्य कहा। उनके द्वारा प्रमुख रूप से भारत के भावी संविधान में अस्पृश्यता निवारण की योजना बनायी। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष भी उनके जन्म दिवस पर पूरे भारतवर्ष में अवकाश की घोषणा करना, उनकी वर्तमान में महत्ता को प्रदर्शित करता है।

CM विष्णुदेव ने कहा; बाबा साहब की दूरदर्शिता लोकतंत्र की नींव

CM विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भी समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों के उत्थान की दिशा में कार्य करते हुए बाबा साहेब के आदर्शों पर चल रही है। डॉ. अम्बेडकर ने कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साप्ताहिक अवकाश की सुविधा देने की पहल की थी। प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महतारी वंदन योजना लागू की है जिसके तहत हर माह एक हजार रूपए प्रदान किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए नई दिल्ली में यूथ हॉस्टल का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिसकी सीटें 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल ग्रामों के विकास हेतु अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्रदेश में अनुसूचित वर्ग के प्री-मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रम की संख्या 486 है, जिसमें 23228 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अस्पृश्यता निवारण हेतु अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक जोड़े में से एक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, उन्हें शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप 2 लाख 50 हजार रूपए प्रदान किया जाता है।

जीरो टॉलरेंस सिस्टम की ओर अग्रसर होता राज्य

ई-आफिस प्रणाली, स्वागतम पोर्टल, समेत भुगतान और खरीदी-विक्री के लिए ऑनलाइन सिस्टम

छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पिछली सरकार पर लगे दाग से सबक लेते हुए भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम बनाने पर प्रमुखता से जोर दिया है। उन्होंने ई-ऑफिस नाम से एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी विभाग, मंत्रालय से लेकर जिलों तक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है, ताकि लोगों की ओर से भ्रष्टाचार, फाइलें रुकने से लेकर गड़बड़ी की शिकायतें न आएँ। इसमें उन टेंडर प्रणाली को भी पूरी तरह से पारदर्शी बनाने पर काम किया जा रहा है, जिसमें अक्सर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिला करती थीं। मुख्यमंत्री साय का मानना है कि बेहतर सुशासन के लिए ई-गर्वनेस प्रणाली एक कारगर उपाय है।

साय ने 21 अगस्त 2024 को महानदी भवन के मंत्रालय में सी तीन पोर्टलों ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि सुशासन के लिए यह प्रणाली एक बेहतर पहल कहलाएगी। इससे शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री साय ने इस ई-प्रणाली और ई-ऑफिस सिस्टम पर काम करने के निर्देश दिए थे। जनदर्शन के माध्यम से भी ऐसी कई शिकायतें सामने आई, जिसमें फाइलें लेट होने के कारण जनता को तकलीफे हुई। फाइलों के बढ़ाने और इसे लेकर कई तरह की अनियमितताएँ सामने आया करती थीं, जिसे लेकर सीएम साय की यह मंशा थी कि एक बेहतर प्रणाली तैयार की जाए, जिससे लोगों की समस्याएँ दूर हो और सारा काम पारदर्शी हो। सरकार गठन के बाद से ही इस तरह की प्रणाली पर वर्किंग शुरू हो गई थी, जिसे अब धीरे-धीरे हर विभाग और उनकी कार्यप्रणाली को ई-प्रणाली से जोड़कर बेहतर बनाया जा रहा है।

जनदर्शन : समस्या का समाधान

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जनदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित करना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। यह कार्यक्रम शासन और आम नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने की अनूठी पहल है। इसके तहत मुख्यमंत्री सीधे आमजन से मिलकर उनको शिकायतें सुनते हैं और संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हैं। इसकी खासियत है पारदर्शिता, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और को बढ़ावा सुशासन देना।

सुशासन एवं पारदर्शिता

- राज्य में जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन।
- छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन। सभी सरकारी विभाग अब आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का करा जेम पोर्टल से करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता के लिए वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य।

शराब घोटाला

नकली होलोग्राम और बिना स्कैनिंग की शराब के जरिए 2161 करोड़ रुपये का घोटाला। ईडी और एसीबी द्वारा कार्रवाई जारी।

कोयला पोटाला

प्रति टन कोयला परिवहन पर अवैध उगाही से 540 करोड़ रुपये का नुकसान। मामले में कार्रवाई जारी।

फाइलों की ट्रैकिंग के साथ मिलेगा रियल टाइम अपडेट

eOffice
A DIGITAL WORKPLACE SOLUTION

सुशासन के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ई-आफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल की शुरुआत एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह कहना है मुख्यमंत्री साय का। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस व्यवस्था के साथ- साथ फाइलों की लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हमने मोदी की गारंटी के माध्यम से यह घोषणा भी की थी। डिजिटल गवर्नेस को हर स्तर पर ले जाने के लिए हम काम कर रहे हैं। साय ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है। तीनों पोर्टल का शुभारंभ प्रदेश में सुशासन स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होगी। गलती की गुंजाइश कम होगी। फाइल किस स्तर पर है, इसकी ट्रेकिंग भी की जा सकेगी।

खनिज और भूमि संबंधी सुधार

खनिज परिवहन पारदर्शिता के लिए ई-ट्रांजिट पास की व्यवस्था पुनः शुरू। इससे राजस्व में वृद्धि। संपत्ति पंजीयन ऑनलाइन भुगतान सुविधा। मध्यम वर्ग को राहतः गाइडलाइन मूल्य पर रजिस्ट्री शुल्क। और रजिस्ट्री में पारदर्शिता के लिए।

सुगम एप करेगा धोखाधड़ी से हिफाजत

- ऑनलाइन सर्च और सत्यापित प्रति (नकल) अब घर बैठे उपलब्ध।
- भूमि विवाद निपटाने के लिए जिओ रिफ्रेसिंग तकनीक का उपयोग।

महत्वपूर्ण डिजिटल पहल

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ (25 दिसंबर 2023)। यह महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए डिजाइन किया गया।

सिंगल विंडो सिस्टम 2.0

उद्योग स्थापना से संबंधित सभी कनीयरेंस एक ही पोर्टल पर। आवेदन की स्थिति सिंगल क्लिक पर उपलब्ध।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-22683361, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी।